फरवरी 2020

₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

नो NRC NPR

14

बदलाव की आहट

26

खास बातचीत अखिलेश यादव

22

R.N.I. No. 68832/97

समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। नौजवानों भविष्य में पार्टी तुम्हारे हाथों में होगी, समाजवादी सिद्धांतों और साहित्य को पढ़ो। किसान, नौजवान और व्यापारी ही देश को शक्तिशाली बनाते हैं।

मुलायम सिंह यादव

संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन
फरवरी 2020

अंदर

खास बातचीत 22

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से समाजवादी बुलेटिन की खास बातचीत में पढ़िए राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों पर उनकी बेबाक राय।

14 कवर स्टोरी

नहीं चाहिए NPR चाहिए हमको रोज़गार

नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमनकारी रवैए के खिलाफ सबसे मजबूत स्टैंड समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने ही लिया है। उन्होंने स्पष्ट भाषा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की निंदा की जिसमें कहा गया था कि धरना प्रदर्शन करने वालों से उत्तर प्रदेश सरकार बदला लेगी।

26 सियासत

बदलाव की आहट

साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव की आहट तेज हो रही है और विकल्प समाजवादी पार्टी ही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से त्रस्त जनता बदलाव की बाट जोह रही है।

दिल्ली चुनाव 04 | आम बजट 2020 06 | ग्राउंड रिपोर्ट 32

प्रिय पाठकों,

समाजवादी बुलेटिन का यह नया अंक बदले हुए रंग-रूप और कलेवर में आपके हाथों में है। इसमें समाचार के साथ विचार का संतुलन बनाये रखते हुए आपके लिए पठनीय सामग्री को हर पन्ने पर समेटा गया है। हम निरंतर ऐसी ही सामग्री लेकर आयेंगे। आशा है आपको बुलेटिन का यह नया रूप पसंद आयेगा। आपकी प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
प्रोफेसर रामगोपाल यादव

/samajwadiparty
bulletinsamajwadi@gmail.com

समाजवादी पार्टी के लिए
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
आस्था प्रिंटर्स, गोमती नगर, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/92

दिल्ली के जनादेश में देश के लिए संदेश

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नफरत, भेदभाव व सांप्रादियक राजनीति बुरी तरह हारी। सत्तर विधानसभा सीटों पर भाजपा दहाई सीटों का आंकड़ा भी न छू सकी और केवल 8 सीटों पर सिमट गई।

ऐसे चुनाव नतीजे तब आए जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके तमाम बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भी लगाई गई थी व भाजपा ने पानी की तरह पैसा बहाया। भाजपा के नेता गली-गली और घर-घर गए। पार्टी के ढाई सौ से ज्यादा सांसद दिल्ली की झुग्गियों और कालोनियों में लोगों को यह समझाते रहे कि भाजपा को वोट दें।

इतना ही नहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव प्रचार को इतना भड़काऊ और सांप्रदायिक रंग दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाजपा नेताओं ने चुनावी मंचों से विपक्षी दलों के नेताओं को खुलकर गद्दार कहा और खुलेआम अपने समर्थकों को उकसाया की उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए।

हद तो तब हो गई जब चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में कुछ भाजपा समर्थकों ने शाहीन बाग में सीएए, एनआरसी के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण धरना में गोली तक चलाई। इस हमलावर और भड़काऊ चुनाव प्रचार के बावजूद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को तवज्जो नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सुनाया।

दिल्ली चुनाव के नतीजे इस ओर संकेत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत भरी राजनीति, समाज को बांटने की उसकी रणनीति और बांटो और राज करो की साजिश के दिन अब लदने लगे हैं। दिल्ली की जनता ने बंटवारे की सियासत के बजाय विकास और काम को तवज्जो दिया। हर तबके के लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। इससे यह भी साफ है कि लोगों को धार्मिक भावनाओं पर बांटने की कोशिशें अब सफल नहीं हो पाएंगी।

दिल्ली के चुनाव नतीजों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि जैसा चुनाव अभियान भाजपा ने चलाया वैसा, चुनाव अभियान लोगों को मंजूर नहीं। देश के बाकी हिस्सों की तरह दिल्ली में भी मतदाताओं में युवाओं की बड़ी संख्या है और नतीजे बता रहे हैं कि इन युवाओं ने भी भाजपा के बंटवारे वाली राजनीति को नकारा है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली चुनाव में प्रचार करते हुए अपने भाषणों से खूब जहर घोला था। लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि वह जहां भी चुनाव प्रचार करने गए वहां भाजपा चुनाव हार गई। यह तथ्य इस संकेत की ओर भी इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गोली मारो और ठोक दो वाली राजनीति जनता को पसंद नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली चुनाव नतीजों ने उत्तर प्रदेश के लिए भी यह स्पष्ट संदेश दिया है कि विकास की राजनीति ही चलेगी भले ही थोड़े समय के लिए जनता को बरगलाने में भाजपा कामयाब रही हो।

काम और विकास के पैमाने पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारों के प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं पीछे हैं। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में चली समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास को ही अपना मुख्य ध्येय बनाते हुए जनता के जीवन की बेहतरी के लिए

कई कार्य किए। यूपी में भाजपा की सरकार के 3 साल के कार्यकाल में ठप हो गए विकास से उपजी समस्याओं को जनता बखूबी समझ रही है। वह वर्तमान सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं की तुलना अखिलेश जी की सरकार से कर रही है और इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि जो काम अखिलेश जी ने अपनी सरकार में करवाए उसकी तुलना में भाजपा की वर्तमान सरकार कहीं टिकती भी नहीं है। निश्चय ही 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते समय अपने इस निष्कर्ष को बखूबी ध्यान रखेगी।

ऐसा नहीं है कि दिल्ली के चुनाव में ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा हो। इससे पहले छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में भी भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को जनता नकार चुकी है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके बाद पश्चिम बंगाल और असम में । भाजपा के पास अपना काम बताने के लिए कुछ है नहीं लिहाजा यह तय है कि वह इन राज्यों में भी अपनी अब तक की अराजक चुनाव शैली पर ही अमल करेगी और चाहेगी कि चुनाव उसके अपने एजेंडे वाले राष्ट्रीय मुद्दों को पर ही लड़ा जाए, लेकिन दिल्ली ने दिखा दिया है कि यदि चुनाव को विकास और स्थानीय मुद्दों व प्रदेश की जरूरतों पर केंद्रित रखा जाए तो भाजपा की राजनीति फेल हो सकती है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों का भाजपा के पास कोई जवाब नहीं होता। वह इन मुद्दों पर अब लगातार घिरती चली जाएगी। न सिर्फ बिहार, बंगाल और असम बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अब उसकी विभेदकारी राजनीति नहीं चलने वाली। दिल्ली के जनादेश से यही संदेश निकला है।

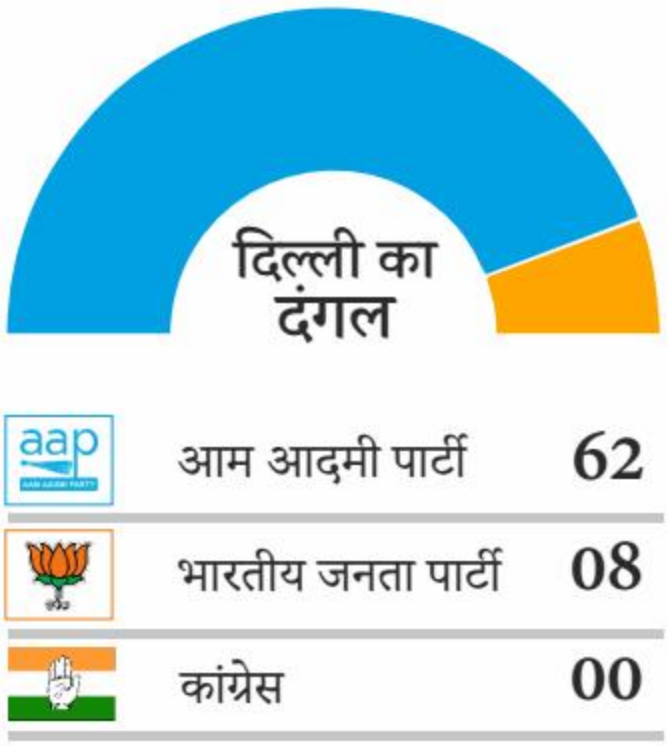

फाइल फोटो

नफरत की राजनीति नाकाम

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिल्ली राज्य विधानसभा के चुनावों में मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल की जीत पर बधाई देते हुए कहा है कि भाजपा की नफरत की राजनीति सफल नहीं हो सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है वहां सत्ता का दुरुपयोग करने के बाद भी भाजपा का जनता के निर्णय के सामने टिक न पाना एक करारा सबक हैं। इस जनादेश का संदेश पूरे देश में जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि भाजपा के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा झूठा है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा के न कोई साथ है, न किसी का विकास हुआ है और न भाजपा पर किसी का विश्वास है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली में भाजपा के स्टार प्रचारक बने घूमते रहे। वे जहां-जहां प्रचार में गए भाजपा का बंटाधार हो गया। "जहां-जहां चरण पड़े संतन के, वहां-वहां भाजपा का सूपड़ा साफ।" दूसरे राज्यों में भी वे जहां प्रचार करने गए थे वहां भी उनका यही रिकार्ड रहा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने धोखा देकर केन्द्र में तो अपनी सरकार बना ली लेकिन एक वर्ष के अन्दर ही दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय विकास के पक्ष में दिया है। दिल्ली की जनता ने बढ़ती बेरोजगारी, मंहगाई, साम्प्रदायिकता के विरोध में मतदान किया।

सीएए, एनआरसी, एनपीआर भी भाजपा की पराजय के कारणों में शामिल है। भाजपा का समाज में नफरत के जरिए ध्रुवीकरण करके मतदान कराने का प्रयास व लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात पहुंचाने की कोशिश को जनता ने नकार दिया।

अखिलेश जी ने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि भाजपा किसी भी बाग को उजाड़ने की ताकत नहीं रखती है। लोकतंत्र में भारतीय समाज का बाग फलता-फूलता रहेगा। भाजपा के झूठ छल प्रपंच को जनता अच्छी तरह समझ गयी है। भविष्य में भी भाजपा की झांसे की राजनीति कामयाब नहीं हो सकती।

आर्थिक अनिवार्यताओं की अनदेखी निजीकरण को बढ़ावा

आर्थिक सर्वेक्षण ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था 42 वर्षों में इतनी खराब न थी। चार दशकों में पहली बार हमारे लोगों की खपत में कमी आ रही है, रोजगार की कमी है, गरीबी और कुपोषण बढ़ने का खतरा है।

अरविन्द मोहन

वरिष्ठ पत्रकार, लेखक

यह कहने में हर्ज नहीं है कि पिछले साल का बजट और उसे बनाने का तरीका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समझ नहीं आया था तो इस बार उनका बजट किसी और को समझ नहीं आ रहा है, और कुछ समझ आ रहा है तो यही कि वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नए पहल करने और देश को मन्दी से उबारने के कदम उठाने का अवसर चूक गई हैं। आम चुनाव के पूर्व पेश अंतरिम बजट तो चुनावी रंग में रंगा था लेकिन जब वित्त जैसे भारी मंत्रालय का जिम्मा सम्भालने वाली निर्मला सीतारमन ने जब बजट पेश किया तो उसमे साफ दिखती आर्थिक मन्दी का जिक्र न था और पूंजीवालों को सीधे सीधे निशाने पर लिया गया था। लेकिन समय नहीं लगा जब निर्मला के लिए आर्थिक मन्दी सबसे बडी चिंता बन गई और तीन चरणों में जो बदलाव किए गए उससे यह चूँ चूँ का मुरब्बा बन गया। अभी भी मन्दी को स्वीकार नहीं किया गया है (उल्टे संसद में इसका खंडन किया गया) लेकिन दो तीन ऐसे अडे कदम उठाए गए हैं जिन्हें मन्दी से बचाव के लिए अनिवार्य माना जा सकता है जैसे बैंक खातो का बीमा बढाकर एक

की जगह पांच लाख करना। पर बाकी किस फैसले को याद किया जाए यह मुश्किल है।

भाषण तो अच्छा था।पौने तीन घंटे चला और फिर भी अधूरा छोडना पडा। प्रधानमंत्री से होड़ लेने वाला था हवाई बातों में और योजना दर योजना घोषित हुई लेकिन फंड का आवंटन और प्रावधान नदारद था। कृषि जैसे क्षेत्र में जब बहुत सारी योजनाओं की घोषणा के बाद धन का जिक्र हुआ (आम तौर पर बजट प्रावधान नहीं घोषित हुआ और बजट के दस्तावेज से देखने का सुझाव दिया गया) तो पता चला कि यह रकम पिछले साल से कम है। प्रतिरक्षा का कुल बजट भी घटा। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत ऊंची ऊंची बाते की गई लेकिन यहां भी यही स्थिति थी, और रेल का बजट किसी को समझ आ गया हो तो उसे लाल बुझक्कड मानना चाहिए। और विदेशी निवेश की राह आसान करने, डिविटेंट टैक्स (डीडीटी) का बोझ कम्पनियों पर से हटाने जैसे फैसलों का मर्म बाजार ने समझा और बजट के साथ ही सेंसेक्स हजार अंक का गोता लगा गया। सरकार की आमदनी बढने-बढाने की सूरत नजर नहीं आती और सारा जोर राजकोषीय घाटे को थामने पर लगता है जिसकी खुली सिफारिश विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करते रहे हैं। कर राजस्व में वृद्धि की गुंजाइश समाप्त सी है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बढानेवाले कदमों की घोषणा नहीं की गई है। इसलिए अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण चाहे जितने सपने दिखाएं असलियत एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण से जाहिर हुआ जिसमें इस साल के विकास दर का प्रोजेक्शन आम अनुमानों से बेहतर बताने की बाजीगरी की गई थी।

अब सब मानते हैं कि इस वित्त वर्ष का विकास दर पांच फीसदी से भी नीचे रहेगा। आर्थिक सर्वे में वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े हासिल करने के बाद उस साल का विकास दर अनुमानित और प्रोजेक्टेड विकास दर से कम मान लिया गया (क्योंकि अब वह कोई मुद्दा नहीं है और वास्तविक आंकड़ों के बाद उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता) और उस कमजोर बेस के आधार पर अगले साल के लिए 6 से 6.5 फीसदी का विकास दर बता दिया। कलाकारी का आलम यह है कि पहली बार सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण में अपने आंकड़ों की जगह विकीपीडिया के दो ग्राफ और आंकड़े लगाए गए थे और शायद यही कारण है कि जयति घोष जैसी अर्थशास्त्री बजट के सारे आंकड़ों को अविश्वास के साथ देखती हैं। पिछली बार विकास दर सात फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया था जिसे आज पांच फीसदी भी नहीं माना जा रहा है। इन कमियों के बावजूद आर्थिक सर्वेक्षण ने माना कि भारतीय अर्थव्यवस्था 42 वर्षों में इतनी खराब न थी। चार दशकों में पहली बार हमारे लोगों की खपत में कमी आ रही है, रोजगार की कमी है, गरीबी और कुपोषण बढ़ने का खतरा है।

सरकार विनिवेश के लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाई है और अब जीएसटी में राज्यो के हिस्से भेजने में देरी से लेकर अपने खर्चों को टालने जैसी चालाकियां करने लगी है। बजट का आकार प्रकार अपेक्षित ढंग से न बढ़ना भी इसी तरह की चालाकी का हिस्सा है जबकि आप सारी कोशिश राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार सारी कवायद करती दिखती है लेकिन बजट में मंदी से लड़ने के उपाय कम ही दिखते हैं अपनी पिछली कटैतियों में वित्त मंत्री ने अमीरों पर लगाए अपने कर वापस लिए थे और कार्पोरेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई किस्म की रियायतें दी थीं। इस पर यह आलोचना हुई कि आम लोगों के जेब में नही है, काम नहीं है, इसलिए आर्थिक गतिविधियाँ और सामानों की मांग नहीं बढ़ सकती। सो इस बार का सबसे चर्चित कदम आयकर में कटौती का उठाया गया जिससे मध्यवर्ग की जेब में कुछ ज्यादा पैसे रह सके। पर पुरानी स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक्जम्शन वाली व्यवस्था को भी बनाए रखने के साथ नई दरें घोषित की गई और किसी भी काबिल दुकानदार की तरह सबसे ज्यादा बचत वाले स्लैब की चर्चा करके यह साफ बता दिया गया कि हम डिडक्शन और एक्जम्शन की व्यवस्था समाप्त करना चाहते है। बजट ही घोषणा से अभी तब पूरी मीडिया और सीए वर्ग यही हिसाब लगाने में लगा है कि करदाता के लिए पुरानी व्यवस्था लाभ होगा या नई से। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस बदलाव की चर्चा चाहे जितनी हो हमारे आपके खाते या फिर सरकार के खाते में भी ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। यह बात इस साल पर ही लागू होने वाली है क्योंकि वित्त मंत्री और इस सरकार को डिडक्शन और एक्जम्शन से जितनी चिढ़ हो, अर्थव्यवस्था और आम लोगों को इससे लाभ था, जबरिया बचत का। जब बीमा लेने या पैसे जमा करने से कर का लाभ दिखता है तो हम कई तरह से

इस बार का सबसे चर्चित कदम आयकर में कटौती का उठाया गया जिससे मध्यवर्ग की जेब में कुछ ज्यादा पैसे रह सके। पर पुरानी स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक्जम्शन वाली व्यवस्था को भी बनाए रखने के साथ नई दरें घोषित की गई और किसी भी काबिल दुकानदार की तरह सबसे ज्यादा बचत वाले स्लैब की चर्चा करके यह साफ बता दिया गया कि हम डिडक्शन और एक्जम्शन की व्यवस्था समाप्त करना चाहते है।

बचत करने की कोशिश करते हैं। बीमा कम्पनियों का धन्धा इस वजह से भी चलता रहा है और हमारे बचत की दर भी काफी अधिक रही है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। पर हाल के दिनों में बचत दर मे कमी आई है क्योंकि हाल की पूरी अर्थनीति बचत की जगह खर्च कराने वाली रही है, बाजार अर्थव्यवस्था का स्वभाव यही है।

2012 में बचत दर अगर 36 फीसदी थी तो अब तीस फीसदी रह गई है। घरेलू बचत की दर में और ज्यादा गिरावट आई है जो 2012 के 23 फीसदी की जगह 2018 में 17 फीसदीही रह गई थी। कहना न होगा कि इस बार के बजट के बाद बचत और घटेगी। मामला सिर्फ बचत का ही नहीं है, बीमा का भी है जिसकी पालिसी, खासकर स्वास्थ्य की, पर भी कर में छूट मिला करती है। अब सरकार इकट्ठा जनता के धन से बीमा लेने देने का खेल चाहती है लेकिन हमारे आपके हाथ में यह विकल्प नहीं रहने देना चाहती। इन डिडक्शन/एक्जम्शन से अप्रत्यक्ष लाभ पाने वाला एक प्रमुख क्षेत्र रियल एस्टेट का है क्योंकि घर की खरीद में मोटा पैसा लगता जिसके मूलधन और सूद पर भी सरकार कुछ छूट देती है। यह कोई दया की चीज नहीं है। चूंकि सरकार लोगों को मकान उपलब्ध कराने की अपनी जबाबदेही का निर्वाह नहीं कर रही है इसलिए वह उन लोगों को राहत देती है जो उसे इस जवाबदेही से मुक्त करते हैं। जब इस तरह की छूट और रियायतें वापस ली जाएंगी तब पहले से ही खस्ताहाल रियल एस्टेट बाजार और परेशान होगा।

सरकार ने दूसरा 'कल्पनाशील' कदम डीडीटी अर्थात डिविडेंट डिडक्शन टैक्स का बोझ कारपोरेट के सिर से हटाकर आम निवेशकों के सिर डालने का किया है। इसके लिए काफी समय से दबाव था लेकिन इस व्यवस्था से बेहतर वसूली हो रही थी इसलिए सरकार इसे चला रही थी। अब बोझ आम निवेशकों के ऊपर डालने के साथ हल्की राहत भी दी गई है लेकिन गणना बहुत मुश्किल हो गई है। इसी तरह स्टार्टअप के कर्मचारियों को कर भुगतान में कुछ समय की रियायत दी गई है जिसका कोई ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है। वित्त मंत्री ने कर के पुराने विवादों को सुलझाने के लिए विवादित रकम का एक हिस्सा देकर आगे बढ़ने का विकल्प दिया है जिससे कितना लाभ होगा यह कहना मुश्किल है। शेयर बाजार शेयर के लांग टर्म कैपिटल गेन पर कर की रियायत मिलने की उम्मीद कर रहा था जो नहीं हुआ। बाजार इसी चलते भड़का।

पर जिस चीज से सबसे ज्यादा हैरानी हुई वह है भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण, इसके लिए निर्गम लाया जाएगा। लेकिन कभी निजी से सरकारी इस कम्पनी ने जिस तरह बीमा के कारोबार और अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाई और आज भी यह जिस तरह क्लेम निपटाने में निजी और विदेशी बीमा कंपनियों से काफी आगे है, उस स्थिति में इसके निजीकरण का तर्क समझना मुश्किल है। सरकार एअर इंडिया बेचने के फैसले के बाद अगर बीमा क्षेत्र को भी इस तरह निजी हाथों में करेगी तो उसके कामकाज पर सवाल उठने चाहिए। विपक्षी दलों को तो इसे राजनैतिक विरोध का विषय भी बनाया जाना चाहिए। निजीकरण का यही जुनून रेलवे के मामले में भी दिखता है। रेल, गाडियों और माल ढुलाई में निजी क्षेत्र को प्रवेश देने के बाद अब दस स्टेशनों को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है।150 गाडियों का संचालन निजी हाथों में सौंपने की घोषणा बजट में की गई। निजीकरण का दूसरा क्षेत्र शिक्षा का रहा जिसकी चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण में भी थी. मेडिकल शिक्षा में विदेशी कालेजों को लाने का फैसला भी घोषित हुआ।

पर कृषि और अन्य क्षेत्र की अनेक भारी भरकम योजनाओं की तरह इस योजना का भी कोई टाइअमलाइन नहीं दिया गया. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में योजनाओं की झड़ी लग गई लेकिन वहाँ भी प्रावधान नदारद थे। योगेन्द्र यादव का मानना है कि कृषि क्षेत्र की सारी घोषणाओं के बावजूद बजट का कुल प्रावधान पिछले साल से कम का ही है, और प्रताप भानु मेहता जैसे जानकारों का कहना था कि वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थीं या पंचवर्षीय योजना यह भेद कर पाना मुश्किल था। लेकिन एक बार फिर से 2022 तक किसानों की आय दो गुनी करने की बात दोहराई गई। बताना न होगा कि 2014 के चुनाव में पांच साल में फसल की कीमत दो गुनी करने की बात की गई थी। खेती के लिए एक अच्छी घोषणा हुई हर पंचायत में भंडारण की सुविधा विकसित करने की। कहना न होगा कि आवारा पशुओं के लिए भी पंचायत स्तर पर कोई केन्द्र विकसित करना पूरी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए काफी लाभकर होगा और इससे कृषि के बाइ प्रोडक्ट का प्रबन्धन भी आसान हो जाएगा।

अब वक्त आ गया है कि मनरेगा का काम किसानों को खेती और पशुपालन में प्रत्यक्ष मदद का हो क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने, ग्रामीण मजदूरी बढाने और खेतिहर मजदूरों आय बढाने में सबसे सक्षम कार्यक्रम वही साबित हुआ है। अब उत्पाद कर और कई दूसरे करों के एक जीएसटी में आ जाने से कीमतें बढ़ने-घटने वाला पुराना राग अलापना बन्द हुआ है, पर इस बार सरकार ने नए सिरे से सीमा शुल्कों में जो बढोत्तरी की है उसका विदेश व्यापार पर असर होगा भले ही उससे सरकारी राजस्व में खास वृद्धि होती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ बार बार की कोशिशों के बावजूद न जीएसटी की वसूली में मनचाही वृद्धि हो रही है न छोटे उद्यमियों/व्यापारियो की मुश्किलें कम हो पा रही हैं। इस बजट में भी जीएसटी से होने वाली तकलीफ कम करने के फैसले हुए हैं वे आम शिकायत वाले हैं या कुछ खास के, यह साफ नहीं है। कार्पोरेट क्षेत्र वाले बतलाओ का मुख्य स्वर तो अपने प्रिय जनों की तकलीफ दूर करना या फायदा कराना है। किसी भी मामले में लोगों, उत्पादको, व्यापारियों की आम शिकायत पर फैसला नहीं हुआ है जबकि होना यही चाहिए था.

कहना न होगा कि बजट का मुख्य स्वर निजीकरण को बढ़ावा देने, सरकारी कंपनियों को निजी हाथ सौंपने, रेलवे में प्राइवेट खिलाड़ियों को घुसाने और बड़े कार्पोरेट घरानों की जेब में कुछ ज्यादा पैसे डालने वाला ही रहा। अर्थव्यवस्था जिस मन्दी, बेरोजगारी, मांग और खपत की कमी से जूझ रही है उनके लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। अगर बैंकों के खाते का बीमा बढा तो वह भी इसीलिए कि बैंक अफवाहों के चलते न डूबे बाजार को उसमें लगी पूंजी उपलब्ध रहे।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

हर पायदान पर डगमग

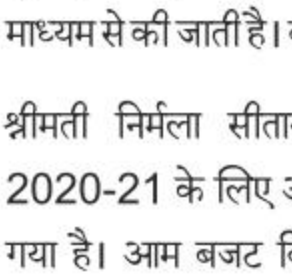

अशोक कैथल

सहायक प्रोफेसर,अर्थशास्त्र,लखनऊ विवि

भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है,जिसे वैश्विक स्तर पर पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। भारत वर्ष अपार संभावनाओं से परिपूर्ण देश है, क्योकिं यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है तथा मानव संसाधन की भी उपलब्धता है, बस आवश्यकता है अच्छे नियोजन की। अच्छे नियोजन के साथ-साथ उपयुक्त मात्रा में पूँजी के विनियोग की। इस पूँजी के विनियोग की आपूर्ति भारत सरकार के द्वारा आम बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र (कृषि, उद्योग, सेवा) को राशि के आवंटन के माध्यम से की जाती है। वर्तमान वित्तमंत्री

श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट पेश किया गया है। आम बजट विभिन्न पायदानों पर विफल होता हुआ दिखता है, इस लेख के माध्यम से इस बजट की कमियों को दर्शाने का प्रयास किया गया है तथा ये इस प्रकार हैः-

भारत में शिक्षित बेरोजगारी लगातार बढती जा रही है, इस बजट में नए इंजीनियरों के लिए स्थानीय निकायों में सालभर इंटर्नशिप, विदेशों में नौकरी के लिए ब्रिज कोर्स संचालित करने रोजगार आधारित शिक्षा के लिए 150 उच्च शिक्षण सस्थानों में डिग्री/डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा की गयी है तथा साथ ही रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की बात की गयी है परंतु इस बात पर जोर नही दिया गया कि नये रोजगार का सृजन कैसे किया जायेगा। 2017-18 के बेरोजगारी के आकड़ों को देखने पर पता चलता है कि यह 6.1 प्रतिशत थी, जो कि 45 साल के अवधि काल में सबसे अधिक थी। वर्तमान में ना तो बाजार में माँग है और ना ही कोई उद्योगपति निवेश करना चाहता है, ऐसी दशा में भारत में रोजगार के नये अवसरों को कैसे बढ़ाया जायेगा तथा सरकार औद्योगिक मंदी एवं माँग की कमी को कैसे दूर करेगी, इसके कोई संकेत 2020-21 के बजट में नहीं दिख रहे है।

वित्तमंत्री ने रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए आवंटित राशि में कमी की है, 2019-20 में-71,001.81 करोड़ रू थी जो कि 2020-21 में 61,500 करोड़ रू की दी गयी है। इस आवंटन राशि में कमी का असर ग्रामीण क्षेत्र में क्रय शक्ति की कमी के रूप में दिखेगा तथा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर हो रहे लोगों के पलायन में वृद्धि भी नजर आयेगी।

सरकार के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अर्तगत गरीबी उन्मूलन के लिए 0.5 करोड़ परिवारों को 58 लाख एस एच जी के साथ जोड़ा गया है परतुं यह सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का लग्भग 55 प्रतिशत हिस्सा निवास कर रहा है और यह सरकार के द्वारा किया गया प्रयास बहुत कम है।

सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय

दिवालिया सरकार दिवालिया बजट

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट बहुत निराशाजनक है। यह दिवालिया सरकार का इस दशक का दिवालिया बजट है। बजट में गांवों, किसानों, श्रमिकों के साथ धोखा किया गया है। 70 प्रतिशत आबादी की भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। बैंक डूबे हुए हैं। रोजगार कहीं है नहीं। किसानों को कुछ नहीं मिला है। गन्ना किसानों का बकाया है।

श्री यादव ने कहा कि इस बजट से गरीब की जिन्दगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। कई निवेशकों के वायदों के बावजूद निवेश नहीं आया है तो आयकर में रोजगार कहां से आएगा? सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। उसे उधार मांगना पड़ रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम, एयर इण्डिया को बेचना पड़ रहा है। जब सामान्य आदमी की आमदनी ही नहीं है तो आयकर में राहत कैसी?

श्री यादव ने कहा कि केन्द्रीय बजट में गिरती अर्थव्यवस्था को सम्हालने और रोटी-रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कोई सोच नहीं दिखती है। इससे जनता का भरोसा टूटा है। महंगाई पर नियंत्रण की कोई ठोस योजना नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है किसानों की आय दुगनी करने की रट लगाए है लेकिन किया कुछ भी नहीं। किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। महंगाईऔर कर्ज से परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

बजट में बेरोजगारों के हाथ फिर निराशा लगी है। कारपोरेट संस्कृति से सराबोर भाजपा से और क्या उम्मीद की जा सकती है? भाजपा नेतृत्व को न तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पता है और नहीं वह गांव-खेती की समस्याओं से अवगत है।

श्री यादव ने कहा कि सरकार की आमदनी घटी है और वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। ऐसे में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करनेवाले झांसा देने वाले बन गए हैं।

को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है, तथा वर्तमान में कृषि विकास दर 2 प्रतिशत है तथा इस आम बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 16 बिदुबों पर आधारित विकास का मॉडल पेश किया है जिसमें-सोलर पैनल लगाने, बिजली पैदा करने तथा उससे पम्प चलाने की बात की गयी है, साथ ही अतिरिक्त बिजली किसान के द्वारा दूसरों को बेचने की बात की गयी है। ये बाते कोरी कल्पना ही प्रतीत हो रही है क्योकि सोलर पैनल लगाने, इसके संचालन, एवं उपयोग के लिए प्रशिक्षण तथा इसकी स्थापना के लिए पूँजी की आवश्यकता है। औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के उत्पादों की माँग बाजार में नही है। और इसके पीछे प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र इन उत्पादों की माँग करता है परंतु वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में घटती हुई क्रयशक्ति लगातार इस माँग को कम तथा प्रभावित करती जा रही है।

किसान को समर्थन मूल्य का लाभ भी नही मिल पा रहा है,क्योंकि बिजली की दरें बढ़ती जा रही है, खाद, कीटनाशक, खरपतवार नाशक एवं कृषि उपकरणों की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। जिसका असर यह है कि कृषि लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

सरकार ने इस बजट में श्वेत क्रान्ति की बात की गयी है परंतु हकीकत कुछ और ही स्थिति बयाँ कर रही है- दूध की कीमत बाजार में तो अधिक है परंतु दूध उत्पादक किसान तक यह लाभाशं नहीं पहुँच पा रहा है जो कि चिंता का विषय है। इस पर वित्तमंत्री जी ने गौर नही किया है।

सरकार ने फिर से नीली क्रान्ति के विस्तितीकरण की बात की है परंतु यह स्पष्ट नही किया की यह कैसे होगा। पिछले बजट 2019-20 में 560 करोड़ रूपये आवंटित थे जिसमें से केवल 455 करोड़ ही खर्च हो पाये है। इस बार सरकार ने 2020-21 के बजट में 570 करोड़ आवंटित किये है परंतु इसका पूर्णरूप से उपयोग हो पायेगा की नही तथा इसका लाभ ग्रामीण जनता को होगा, इस विषय को स्पष्ट नही किया है।

सरकार के समक्ष वर्तमान आर्थिक परिवेश में दो चुनौतियाँ अति महत्पवूर्ण है पहली कि राजकोषीय घाटे को कैसे कम किया जाये तथा आर्थिक मंदी को दूर करके आर्थिक विकास दर को कैसे बढ़ाया जाय। 2019-20 के बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.3 प्रतिशत रखा गया था जो बाद में बढ़कर 3.8 प्रतिशत हो गया था वही 2020-21 के बजट में यह लक्ष्य 3.5 प्रतिशत रखा गया है जिसको कम करना इस आर्थिक परिदृश्य में तो मुश्किल ही दिखता है।

चालू वित्त वर्ष के बजट में घोषित रकम के अतिरिक्त उधार लेना पड़ा, जो जीडीपी के 0.7 प्रतिशत के बराबर है। आगामी वर्ष में यह राशि बढ़कर जीडीपी के 0.8 प्रतिशत के बराबर होने की उम्मीद है, इससे तात्पर्य यह है कि इन दोनो वर्षों में वास्तविक वित्तीय घाटा 4.0 से 4.5 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है।

उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार के लिए सरकार एलआईसी का आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव) लाना चाहती है। यह कोई सुधार नही है पूर्व में भी इस सरकार के द्वारा एयर इडिंया, बीएसएनएल, ओएनजीसी, एचएएल तथा भारतीय रेल जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओ को प्रभावित करने का प्रस्ताव लाया जा चुका है जो सही नही है ये सब संस्थाए सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रोजगार दाता संस्थाएँ रही है तथा आर्थिक सहयोग भी करती रही है।

वर्ष 2020-21 के बजट में एससी तथा ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए 85,000 करोड़ रूपये आवंटित किये गये है, परतुं यह स्पष्ट नही किया गया है कि एस सी वर्ग पर कितना तथा ओबीसी वर्ग पर कितना खर्च होगा। ऐसे में भ्रम व्याप्त रहेगा। अगर हम 2019 के अतंरिम बजट पर नजर डालें तो पायेगें की अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए व्यय का अलग आवंटन था।

यह बजट अधिकतर क्षेत्रों के लिए अलाभकारी प्रतीत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न उत्पादन, रोजगार की कमी, माँग की कमी, पूँजी की कमी, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की कमी, बेहतर शिक्षा की कमी से ग्रसित है।

सरकार का यह बजट कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों के लिए अलाभकारी प्रतीत होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न उत्पादन, रोजगार की कमी, माँग की कमी, पूँजी की कमी, सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों की कमी, बेहतर शिक्षा की कमी से ग्रसित है। आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिये ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, केवल घोषणाएँ करने, लोक लुभावन बातें तथा आशावादी बातें करने से स्थिति में सुधार नही होगा बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल प्रायासों को करना होगा जो समाज के कल्याण में वृद्धी कर सकें। यहाँ कुछ लोगों के कल्याण की बात नही हैं बल्कि सभी के कल्याण की बात है।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

काम से बड़ा कोई धर्म नहीं विकास से बड़ी कोई नीति नहीं

निष्ठा से हर काम करना और सदा करते रहना ही मेरा प्रथम धर्म है। समाज की बेहतरी के लिए नित नए काम की परिकल्पना करते रहना मेरी रुचि है। सिर्फ राज करना मेरी नीति नहीं। समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का उत्तरोत्तर विकास करना ही मेरी प्रमुख नीति है। आपको पूरे विश्वास के साथ वचन देता हूँ कि मैं सदैव अपने धर्म पर चलता रहूँगा और समाजवादी नीतियों को निभाता रहूँगा।

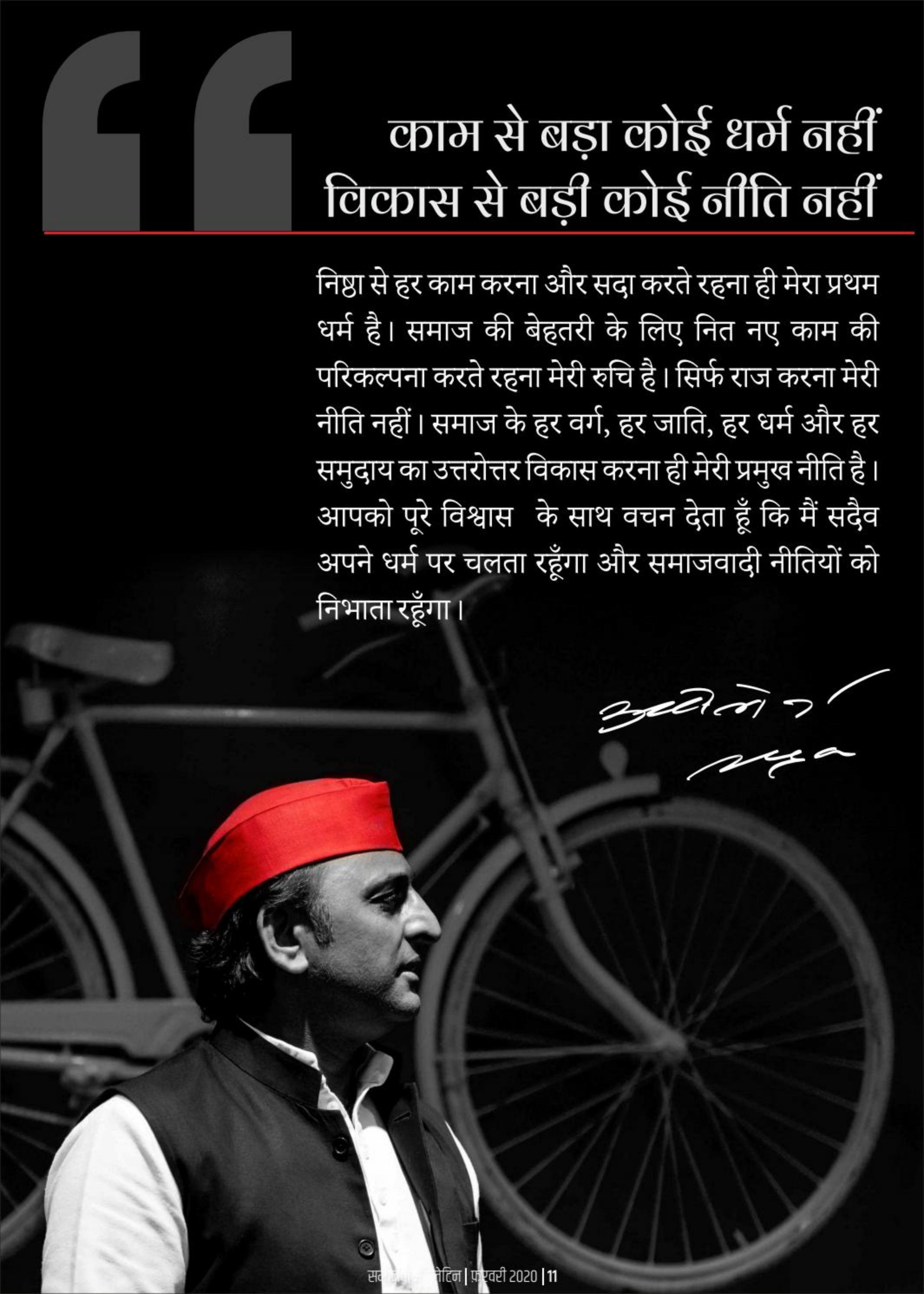

लोकतंत्र जिंदाबाद

सरकार मनमानी पर उतारू है और जनता सत्याग्रही तरीके से विरोध जता रही है। नागरिकता के नए कानून , एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ उत्तरप्रदेश के कई शहरों में यही तस्वीर है। महिलाएं , बुज़ुर्ग , युवा और समाज के सभी वर्गों के लोग सरकार की तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपने गुस्से का इज़हार कर रहे हैं । लोकतंत्र बचाने की यह लड़ाई लगातार जारी है ।

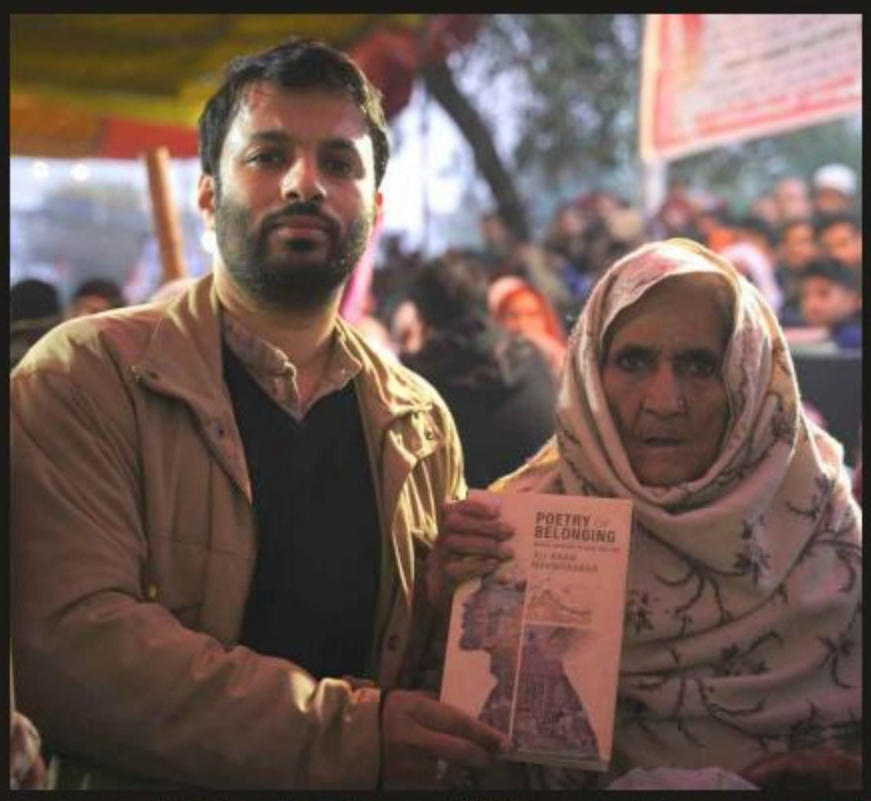

DAY
HEEN BAGH PROTEST
ainst CAA NRC NPR

देश बचाओ - देश बचाओ
NO CAA
NO NRC

नए नागरिकता कानून के खिलाफ लखनऊ कलेक्ट्रेट में शांतिपूर्ण धरना दे रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी

नहीं चाहिए NPR चाहिए हमको रोज़गार

विकास पर बहस से भागती भाजपा

दुष्यंत कबीर

नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर व एनसीआर के जरिए विभाजनकारी राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों के खिलाफ देशव्यापी नाराजगी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर शुरू से ही जनता के पक्ष में खड़े होकर भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया है कि मुद्दों को भटकाने की उसकी राजनीति नहीं चलने दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने नागरिकता कानून में संशोधन के तत्काल बाद यह बयान दिया था कि यह संविधान का उल्लंघन है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने एनपीआर लागू करने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद और ज्यादा सख्त तेवर दिखाते हुए खुला ऐलान किया कि वे एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि देश के लिए ज्यादा जरूरी है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। अखिलेश जी ने नारा दिया, 'नहीं चाहिए एनपीआर- चाहिए हमको रोजगार।'

उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि एनपीआर का फॉर्म नहीं भरने में वे भी उनका साथ दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उन्होंने मन बना लिया है कि एनपीआर में न तो फॉर्म भरेंगे न कोई कागज दिखाएंगे। यहां यह उल्लेखनीय है कि नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में जनता के स्वत:स्फूर्त आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादती से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से अखिलेश जी लगातार मिल रहे हैं।

उन्हें पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है, वहीं परिजनों को अखिलेश जी भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। उनकी

नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में जनता के स्वत:स्फूर्त आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादती से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से अखिलेश जी लगातार मिल रहे हैं। उन्हें पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है, वहीं परिजनों को अखिलेश जी भरोसा दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है।

सीएए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ जनता में व्यापक आक्रोश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं एवं बच्चियां सर्वाधिक असुरक्षित हैं। भाजपा राज में उन्हें हर दिन अपमानित किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में धरना दे रही महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल महिला होते हुए भी महिलाओं के प्रति भाजपा सरकार द्वारा बर्बरता पूर्ण व्यवहार होना पूर्णतया अलोकतांत्रिक एवं दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शनों में महिलाओं की भागीदारी प्रशासन को चुनौती लगती है। मातृशक्ति को अपमानित करके भाजपा को तो कुछ नहीं हासिल होना है हाँ, जागृत मातृशक्ति के आगे सरकार नहीं टिक पाएगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि शांति पूर्वक धरना देना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख तो संविधान की प्रस्तावना में भी है लेकिन भाजपा सरकार को असहमति और विरोध से खासा एलर्जी है। आजमगढ़ के बिलरियागंज इलाके में जो हुआ उससे उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा बेनकाब हुआ है। यहां बर्बरता की सभी हदें पुलिस ने पार कर दी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रही माता-बहनों पर बेरहमी से लाठीचार्ज करना और पथराव करना किस ट्रेनिंग का हिस्सा है?

अखिलेश जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इटावा, प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर और अन्य कई शहरों में महिलाएं बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन में भाग ले रही हैं। उनके विरुद्ध शासन-प्रशासन द्वारा लगातार उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में ठंड से कांपती महिलाओं से कम्बल छीन लिए जाते हैं। आजमगढ़, इटावा, कानपुर में महिलाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं। बड़ी तादाद में महिलाओं की गिरफ्तारियां हो रही है। धरने में शामिल महिलाओं के घरों में नोटिस जारी कर भयभीत किया जा रहा है। निर्दोषों को फर्जी केस में फंसा कर जेल भेजा जा रहा है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा राज में महिलाओं के दुःख दर्द की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। निर्दोष महिलाओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। बच्चों तक पर मुकदमें कायम किए जा रहे हैं। सरकार की क्रूरता की हद तो यह है कि नाबालिग बच्चों को भी जेल भेजा जा रहा है। धरने पर बैठी महिलाओं को भोजन-पानी पहुंचाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। पुलिस का व्यवहार बहुत अनैतिक और निर्ममतापूर्ण है । भाजपा सरकार के विरोध में आए लोगों पर प्रशासन द्वारा तरह-तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। उनके घरों में दबिश डालने, गिरफ्तारी करने के अलावा प्रशासन जुर्माने की नोटिसें जारी कर रहा है। अलीगढ़ में एक हजार लोगों को नोटिसें जारी कर पूछा गया है कि उन पर क्यों न कार्रवाई की जाए? इलाहाबाद, वाराणसी और अन्य कई जनपदों में भी हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर इसी तरह उत्पीड़न की कार्यवाहियां हो रही है।

इस पहल का बहुत सकारात्मक असर इन परिवारों व समाज पर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधि मंडल भी कई पीड़ित परिवारों से मिला है। इन परिवारों के साथ खड़े होने का सिलसिला जारी है।

नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के दमनकारी रवैए के खिलाफ सबसे मजबूत स्टैंड भी अखिलेश जी ने ही लिया। उन्होंने स्पष्ट भाषा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की निंदा की जिसमें कहा गया था कि धरना प्रदर्शन करने वालों से उत्तर प्रदेश सरकार बदला लेगी। अखिलेश जी ने अपने बयान में कहा कि धरना प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और लोगों के इस अधिकार के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री यदि बदला लेने जैसी बयानबाजी करेंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक स्थिति है। पुराने लखनऊ में घंटाघर पर नागरिकता कानून और एनपीआर के खिलाफ लगातार चल रहे महिलाओं के धरना प्रदर्शन के खिलाफ उत्तर

विकास के मुद्दे पर बहस करने की अखिलेश जी की चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आया।

प्रदेश सरकार के नकारात्मक रवैए की भी अखिलेश जी ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने धरना दे रहीं महिलाओं के कंबल इस कड़कड़ाती सर्दी में पुलिस द्वारा उठाकर ले जाए जाने को अमानवीय करार दिया।

नए नागरिकता कानून और एनपीआर पर अखिलेश जी के स्पष्ट स्टैंड से बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक बयान में भाजपा के नेता अमित शाह ने अखिलेश जी को चुनौती दी कि एनपीआर पर उनके साथ बहस करें। इस पर तीखा पलटवार करते हुए अखिलेश जी ने बयान जारी किया कि भाजपा नेताओं को अगर बहस करनी है तो विकास के मुद्दे पर बहस करें। स्थान व समय बता दें और कर लें विकास पर बहस, लेकिन जैसा कि स्वाभाविक था भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अखिलेश जी की चुनौती पर कन्नी काट गए।

विकास के मुद्दे पर बहस करने की अखिलेश जी की चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने नहीं आया। भाजपा नेताओं का यह पलायन ही साफ करता है कि विकास से उनका कोई वास्ता नहीं। उन्हें सिर्फ समाज में बंटवारा करने और राज करने की नीति पर अमल करना है लेकिन नागरिकता संशोधन कानून, एनसीआर एनपीआर के मुद्दे पर जनता की एकजुटता ने भाजपा की पोल खोल दी है। समाजवादी पार्टी जनता की इस एकजुटता और संघर्ष के जज्बे के साथ मजबूती से खड़ी है।

चाहे केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, विकास के मोर्चे पर इन सरकारों के पास न दिखाने के लिए कुछ है न आगे कुछ करने की कार्ययोजना। अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि भारत गंभीर आर्थिक मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसानों की हालत खराब है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आ रहा है जिनका जनसरोकारों से कोई वास्ता नहीं। नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर पर भाजपा की बयानबाजी भी भी ऐसे ही मुद्दे हैं। इस रवैए से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने नोटबंदी जैसे बेतुके और अटपटे फैसले से देश और समाज को हुए नुकसान के दिनों की यादें ताजा कर दी हैं।

> ***नोटबंदी के दौरान जनता को अपने ही पैसे निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा था। नए नागरिकता कानून और एनपीआर में भी सरकार ने ऐसे दस्तावेजों की अपेक्षा की है जिनको जमा कर पाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि असंभव है।***

नोटबंदी के दौरान पूरे देश की जनता को अपने

क्या हैं तथ्य, क्यों है विरोध

- संसद से पास हुए किसी कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए तो उसकी संवैधानिकता पर कोर्ट फैसला ले सकता है। नागरिकता संशोधन कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

- यह सही है कि नागरिकता संशोधन कानून 3 पड़ोसी देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दिए जाने संबंधित है लेकिन इसका भारत में इतना विरोध इसलिए है क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने कई भाषणों और बयानों में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी दोनों को जोड़कर पेश किया है।

- यह सही है कि एनआरसी अभी तक आया नहीं है लेकिन फिर भी इसके विरोध की मुख्य वजह आशंका है। भारत की आबादी के बहुत बड़े हिस्से को यह लगने लगा है कि नागरिकता कानून कि जरिए देर-सबेर एनआरसी पर अमल किया जाएगा और एनआरसी के तहत जो अपनी नागरिकता नहीं साबित कर पाएंगे उन्हें डिटेंशन सेंटरों में बंद कर दिया जाएगा। संसद में सवालों के जवाब में सरकारी मान चुकी है कि उसने असम में डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं। ऐसे ही खबरें आती रही हैं कि कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसे सेंटरों का निर्माण चल रहा है।

- भाजपा सरकार के राज में हुई नोटबंदी के दौरान देश भर में हुई अफरा-तफरी सबको याद है। ऐसे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि नागरिकता की जांच होने लगे तो करीब 135 करोड लोगों की जांच करना कितनी बड़ी कवायद होगी। जांच प्रक्रिया में थोड़ी सी गड़बड़ी भी करोड़ों लोगों को मुश्किल में डाल देगी।

- इसे असम में एनआरसी की प्रक्रिया में हुई चूक से भी समझा जा सकता है। वहां करीब 19 लाख लोग सूची से बाहर हो गए थे जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू थे। असम में एनआरसी में लोगों को अपने पूर्वजों के 1971 से पहले भारत में होने के दस्तावेज जमा करने थे और फिर उनसे अपना रिश्ता साबित करने से संबंधित कागजात भी जमा करने थे।

- सरकार के बयान में कहा जा रहा है कि नागरिकता कानून में उन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो वहां धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे हैं लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में कहीं भी धार्मिक प्रताड़ना नहीं लिखा हुआ है। यह सवाल भी उठ रहा है यह कैसे तय होगा कि कोई धार्मिक तौर पर प्रताड़ित है।

ही पैसे निकालने के लिए लाइन में लगना पड़ा था, वैसे ही नागरिकता कानून और एनपीआर में भी सरकार ने ऐसे दस्तावेजों की अपेक्षा की है जिनको जमा कर पाना न सिर्फ मुश्किल बल्कि असंभव है। सरकार चाहती है कि जनता अपने दस्तावेज और कागज लेकर लाइन में लगी रहे, लेकिन वह यह नहीं बता रही है कि अपने माता-पिता के जन्म स्थान और जन्म तारीख जानकारी देने जैसे कागजातों की जो अपेक्षा की गई है वह कितने लोग मुहैया करा पाएंगे। ठीक इसी तरह, क्या गांव देहात में रहने वाले लोग अपनी संपत्ति से जुड़े कागज दिखा पाएंगे? यायावरी जीवन जीने वाले संपेरा समुदाय जैसे समूह कहां से कागज ला कर दिखाएंगे और यह साबित करेंगे कि वह भारत के नागरिक हैं? अखिलेश जी ने अपने बयानों और भाषणों में लगातार इन मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वे लगातार कह रहे हैं कि यह सरकार लोगों को लाइन में लगाने वाली सरकार है।

स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर सपा के नेताओं - कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के काकोरी से साईकिल यात्रा निकालकर सीएए व एनपीआर का विरोध किया

- विरोध इस बात पर भी है कि भारत को बिना धर्म को आधार बनाए धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को शरण देनी चाहिए क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत के संविधान में भी इसके धर्मनिरपेक्ष होने का स्पष्ट उल्लेख है।

- एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या शरणार्थी सिर्फ पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान और बांग्लादेश से ही भारत आते हैं? क्योंकि श्रीलंका से आए शरणार्थी काफी समय से भारत की नागरिकता की मांग कर रहे हैं लेकिन नागरिकता का नया कानून इनके बारे में खामोश है।

- एनपीआर या नेशनल पापुलेशन रजिस्टर भारत में सामान्य रूप से रहने वालों का एक रजिस्टर है और भारत में रहने वालों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यह 2021 की जनगणना का एक हिस्सा होगा। अपडेट का काम असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक चलेगा। इसे सबसे पहले वर्ष 2010 में लाया गया था और उसे अपडेट करने का काम वर्ष 2015 में घर-घर हुए सर्वे के तहत किया गया था।

- अब एनपीआर को फिर से एक बार अपडेट करने का काम 2020 अप्रैल से सितंबर तक अगले साल होने वाली जनगणना के तहत किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो डेटाबेस तैयार होगा उसमें जनसंख्या की जानकारी के साथ बायोमेट्रिक भी शामिल होगा।

- देश देश की आबादी के एक बड़े हिस्से और राजनीतिक तबके का मानना है कि एनपीआर को एनआरसी से अलग कर नहीं देखा जा सकता है। उसी तरह नए नागरिकता कानून के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसे एनआरसी से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए। यह आशंका है कि जनगणना के नाम पर दोनों को अंजाम देने की तैयारी है। 2010 के एनपीआर में 15 बिंदुओं पर डाटा जुटाया गया था लेकिन इस बार के एनपीआर में माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान के अलावा पिछले निवास स्थल की जानकारी भी मांगी गई है। ऐसे दस्तावेज़ जुटा पाना कई लोगों के लिए बेहद मुश्किल काम होगा। इसलिए माना जा रहा है कि इसके जरिए भारत में रहने वाले लोगों के बड़े हिस्से को घुसपैठिए के रूप में चिन्हित करने की मंशा है।

- 30 जुलाई 2014 को तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि सरकार ने एनआरसी बनाने का फैसला किया है और यह एनपीआर के डाटा के आधार पर ही किया जाएगा। गृह मंत्रालय की वर्ष 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया था कि एनपीआर, एनआरसी का पहला चरण है। यही वजह है कि कई राज्य सरकारों ने एनपीआर की कार्यवाही न करने का ऐलान किया है।

- विरोध और आशंका की एक वजह यह भी है कि केंद्र सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे लोगों ने इन दोनों पर परस्पर विरोधी बयान दिए हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्री कई मौकों पर 'क्रोनोलॉजी' समझाते हुए यह कह चुके हैं कि नया नागरिकता कानून, एनपीआर और इन एनआरसी एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है वही प्रधानमंत्री इसके उलट यह कहते हैं कि एनआरसी के बारे में कोई फैसला ही नहीं हुआ है।

अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी है कि भारत गंभीर आर्थिक मंदी के दौर में प्रवेश कर चुका है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, किसानों की हालत खराब है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे लेकर आ रहा है जिनका जनसरोकारों से कोई वास्ता नहीं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर सदन तक नागरिकता कानून और एनपीआरसी खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और यह सिलसिला लगातार जारी है।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल में सपा के विधायकों

नागरिकता संशोधन अधिनियम

सांविधानिक अधिकारों का हनन

क़ानूनी पहलू

देवेन्द्र उपाध्याय

एडवोकेट

भारत की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन लगातार बढ रही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 135 करोड़ है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों का दायित्व है कि सभी भारत के नागरिकों को सांविधानिक मूल अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद -15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का का प्रतिषेध, अनुच्छेद -16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार उपलब्ध कराने एवं मूल अधिकारों में किसी नागरिक को वंचित होने से बचायें। सांविधानिक मूल अधिकारों के संदर्भ में हाल में बने नागरिकता संशोधन अधिनियम को देखा जाना प्रासंगिक है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को, जो 31 दिसम्बर, 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुए और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा - 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों या उसके अधीन किये गये किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गयी है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी के रूप मे नहीं माने जाएंगे।

उपरोक्त उपबन्ध से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे घुसपैठिये जिनको भारत में बिना पासपोर्ट पकड़ लिए जाने पर अब तक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराया जाता रहा है, उनके खिलाफ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा - 3 की उप धारा (3) द्वारा पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जाता रहा है, उन सभी को अब भारत का नागरिक बना दिया जायेगा, उनके खिलाफ पंजीकृत आपराधिक मुकदमा वापस ले लिया जायेगा एवं उनको भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी सांविधानिक मूल अधिकार हासिल होंगे।

जैसे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार,अनुच्छेद -15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद -16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार उपलब्ध अधिकार प्रदान कर दिये जायेगे। यानी उस आपराधिक व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाकर उसको सरकारी नौकरी में आने, चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने, भारत सरकार से मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा लेने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त हो जायेगे। जिसके कारण पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों के सांविधानिक अधिकारों का हनन होगा।

यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि एनआरसी जिस प्रदेश, यानी असम में लागू हुयी है, वहां पर भारत के समस्त वर्ग के नागरिकों को दिनांक 24.03.71 से पूर्व के कागजात दिखाने पड़े परन्तु नागरिकता संशोधन

अधिनियम के अन्तर्गत 31 दिसम्बर 2014 या उससे पूर्व बिना पासपोर्ट के कोई घुसपैठिया, जो अफगानिस्तान, बंग्लादेश, या पाकिस्तान से आया है उनके आपराधिक मुकदमें समाप्त करके, बिना कागज नागरिकता प्रदान करके सभी सांविधानक अधिकार प्रदान कर दिये जायेगे। जो भारतीय नागरिकों के सांविधानिक मूल अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अधिकार का हनन है। अब प्रश्न यह है कि भारत का मुस्लिम इतना चिंतित क्यों है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें असम की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा जहां मूल रूप से एनआरसी लागू किया गया और जहां पर 1971 से पूर्व के दस्तावेज भारतीय नागरिकों से मांगे गये, जिसमें लगभग 19 लाख भारतीय नागरिकों को बाहर कर दिया गया था।

इन भारतीय नागरिकों में सबसे ज्यादा वैसे लोग हैं जो गरीब हैं व जिन्होंने भारत में अपनी रोजी-रोटी से ज्यादा नहीं सोचा था या यूं कहे उनकी गरीबी ने कभी कोई दस्तावेज बनाने के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। अब नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाने से उपरोक्त 19 लाख लोगों में से हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाइयों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जायेगी लेकिन उपरोक्त 19 लाख लोगों में सिर्फ मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को भारत की नागरिकता वापस नहीं मिल पायेगी।

अतः नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से सबसे ज्यादा चिंतित भारत का मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है। मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारत के उन गरीबों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों के लिए है, जिन्होंने सिर्फ नमक-रोटी से ज्यादा कभी नहीं सोचा, जिनको अभी तक सम्पन्न लोगों द्वारा प्रताड़ना ही दी जाती रही, उन्होंने भारत में अभी तक कोई भूमि नहीं खरीदी, जिनके पास अपनी रोजी-रोटी के सिवाय और कुछ सोचने का मौका नहीं है। वह अब दस्तावेज दिखा पाने के अभाव में भारत से बाहर हो जायेंगे।

सीएए आन्दोलन में पुलिस की ज्यादती से मारे गए कानपुर के युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता देते हुए सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव ।

और विधान परिषद सदस्यों ने पुरजोर तरीके से एनपीआर और नागरिकता कानून के खिलाफ सरकार को घेरा। वही लोकसभा और राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ संसद में सपा ने मतदान किया जबकि सड़कों पर भी सपा के कार्यकर्ता लगातार मुखर हैं।

जनता परिवर्तन के लिए बेताब, भविष्य समाजवादियों का

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ***अखिलेश यादव*** *ने विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनपदों के उनके दौरों में लोगों की भरपूर भीड़ उमड़ रही है । उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति और तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार* ***रंजीव*** *को दिए गए साक्षात्कार में श्री अखिलेश यादव ने बेबाकी से अपनी राय दी। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:*

सीएए, एनपीआर व एनआरसी पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है?

हमारा देश संविधान से चलता है और सीएए, एनपीआर व एनआरसी की मौजूदा कवायद संविधान के कायदों के खिलाफ है, लिहाजा समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी। देश का संविधान बनाते समय बाबा साहब डा.भीमराव अम्बेडकर एवं संविधान सभा ने नागरिकता के लिए जो कानून बनाया था, भाजपा ने उसे असंवैधानिक तरीके से बदल दिया है। संविधान निर्माताओं ने नागरिकता कानून में धर्म और जाति का

भेदभाव नहीं किया था, लेकिन भाजपा अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति पर चलते हुए समाज को धर्म और जाति में बांटकर सरकार चलाना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि "हमें नहीं चाहिए एनपीआर, चाहिए हमको रोजगार।" "कागज नहीं दिखाएंगे" का ऐलान सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने ही किया। मैं खुद सार्वजनिक मंच से ऐलान कर चुका हूं कि मैं एनपीआर का फॉर्म नहीं भरूंगा।

आप लगातार यह कह रहे हैं कि सीएए, एनपीआर दरअसल गरीबों के खिलाफ है, इसकी थोड़ी व्याख्या कीजिए?

सीएए, एनपीआर और एनआरसी पूरी तरह गरीबों के खिलाफ है। पुराने समय के लोगों के पास अपना जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होता था, अब गरीब कहां से अपने माता-पिता का जन्म और निवास प्रमाण पत्र लाएगा। यह कानून मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, यह गरीबों के खिलाफ है। गांव में तो लोगों के पास अपने घर का भी कागज नहीं है। यही नहीं उत्तर प्रदेश में कई रजवाड़ों के राजा और महाराजाओं के पास भी उनके महलों के कागज नहीं होते थे। बंजारों और सपेरों जैसी घुमंतू बिरादरियों के साथ भी यही समस्या है। ये लोग किस कागज से साबित करेंगे अपनी नागरिकता? भाजपा ने एक बार नोटबंदी कर गरीबों को लाइन में लगा दिया था, फिर कागज बनवाने के लिए सबको लाइन में लगवाने की साजिश कर रही है। जिससे लोग इनसे बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और महंगाई पर सवाल न पूछ पाएं। असम से एनआरसी की बात शुरु हुई वहां के लोग इससे कितने परेशान है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। असम में एनआरसी के लिए बड़ी संख्या में हिन्दू कागज नहीं दे पाए। जिसके बाद भाजपा ने कानून ही बदल दिया।

भाजपा सरकार नागरिकता के नए कानून को सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। आपको क्या लगता है?

जब से भाजपा की सरकारें आई हैं देश के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं,

अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे नाकाम प्रयोगों के बाद अब भाजपा सरकार नागरिकता कानून में बदलाव का नया शिगूफा लेकर आई है क्योंकि उसे बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है, भेदभाव की राजनीति करनी है, भारतीयों को जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़वाना है। यह सब इसलिए क्योंकि भाजपा सरकार नौजवानों को नौकरी, रोजगार नहीं देने वाली है। किसानों का भला कर नहीं सकती। अर्थव्यवस्था में वह सुधार कर नहीं सकती, कोई विकास कार्य वह नहीं करेगी। वह देश की जनता को उलझा कर शासन करना चाहती है। इसलिए उसने ऐसा माहौल बना रखा है, लेकिन लोकतंत्र में असली ताकत जनता की होती है और जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। वह सही समय पर वह विवेकपूर्ण फैसला भी करेगी। विकास ही सांप्रदायिकता को हराएगा क्योंकि लोग प्रगति, शांति और विकास चाहते हैं न कि नफरत व गुस्से कि राजनीति।

क्या भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर राजनीति को जानबूझकर दरकिनार कर रही है?

बिल्कुल जानबूझकर दरकिनार कर रही है क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में सुधार, रोजगार, किसान, नौजवान, महंगाई और विकास मुख्य राजनीतिक एजेंडा बन गए तो भाजपा सरकार के पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वह कभी नहीं चाहेगी कि विकास मुद्दा बने। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार में यही तो किया उसने, लेकिन जैसा मैंने कहा, भाजपा का यह तौर-तरीका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। जनता बहुत होशियार है।

आपने विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को खुली बहस की चुनौती दी है, क्या आपको लगता है इसके लिए तैयार होंगे?

> ***सीएए, एनपीआर और एनआरसी पूरी तरह गरीबों के खिलाफ है। गांव में तो लोगों के पास अपने घर का भी कागज नहीं है। ये लोग किस कागज से साबित करेंगे अपनी नागरिकता? भाजपा नोटबंदी के बाद फिर कागज बनवाने के लिए सबको लाइन में लगवाने की साजिश कर रही है।***

कतई नहीं तैयार होंगे, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए तो मेरी चुनौती का जवाब ही नहीं दिया। विकास पर बहस हो जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। उत्तर प्रदेश में 5 साल की सरकार में हमने विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उसे जमीन पर उतार कर भी दिखाया। समाजवादी पार्टी हवाई बातें नहीं करती बल्कि हकीकत में करके दिखाती है। हमने जो विकास करवाया लोगों के सामने है। अभी लखनऊ में रक्षा उपकरणों की जो प्रदर्शनी "डिफेंस एक्सपो" लगी, उसमें सेना के जवानों ने गोमती नदी में जिस सहूलियत से अपने शौर्य और हुनर का प्रदर्शन किया वह इसलिए संभव हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया थ। इतना ही नहीं, इस डिफेंस एक्सपो में दिल्ली से शामिल होने के लिए कई बड़ी कंपनियों के लोग उसी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे से आए जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनवाई थी। कहने का मतलब यह की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले 3 साल से समाजवादी पार्टी की सरकार में करवाए गए विकास कार्यों के भरोसे ही चल रही है। उन विकास योजनाओं को अपना बताकर फिर से फीता काट रही है। इसलिए भाजपा के नेता हमसे कभी विकास पर बहस के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पता है उनके पास कहने के लिए धेले भर की उपलब्धियां नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश के विकास के मामले में समाजवादियों के पास गिनाने को लंबी फेहरिस्त है।

आजमगढ़ में सीएए के खिलाफ धरना दे रही महिलाओं पर पुलिस ने रात के अंधेरे में लाठीचार्ज किया। इसे कैसे देखते हैं आप?

यह बर्बरता की पराकाष्ठा है। शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। भाजपा सरकार इन लोकतांत्रिक अधिकारों को दमन के जरिए कुचलना चाहती हैं लेकिन इससे विरोध की आवाजों को दबाया नहीं जा सकता। आप देखिए न, कैसे पिछले कई दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आजमगढ़ की घटना के बाद समाजवादी पार्टी बहुत सक्रियता से पीड़ित और प्रभावित लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई। जो घायल हुए थे उनके समुचित इलाज की व्यवस्था करवाई और जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई सुनिश्चित करवाई गई। वहां हमारी पार्टी के सभी विधायक व पदाधिकारी लगातार लगे रहें। मैंने लखनऊ से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल भी तत्काल आजमगढ़ भेजा। समाजवादी पार्टी सरकारी दमन का विरोध

करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जनता के साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे। यही समाजवादी सिद्धांत हैं।

आप लंबे समय से राजनीति में हैं, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। सीएए, एनआरसी के खिलाफ देशभर में आंदोलन का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। भारत में यह विरोध प्रदर्शनों कि एक नयी तस्वीर है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं?

यह विरोध प्रदर्शन स्वयं में बहुत मजबूत है, ऐसा पहली बार हो रहा है जब महिलाएं इसका नेतृत्व कर रही है, यह बेहद प्रेरणादायक और हौसला आफजाई करने वाला है, इससे लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है, हमने अतीत में कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व महिलाओं को करते देखा है लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर महिलाओं और यहां तक की कॉलेजों व विश्वविद्यालयों की छात्राओं को सड़क पर उतर कर सरकार की बांटो और राज करो की नीति की मुखालफत करना इस सदी की अब तक की अहम घटनाओं में शामिल है।

देशव्यापी जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। आपने कई मौकों पर कहा है कि जातियों की भी गिनती की जाए। अपनी इस मांग को थोड़ा समझाइए?

पिछली बार जनगणना के समय जातीय गणना को लेकर बहस हुई थी लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जातीय गणना नहीं कराया। अब भाजपा की सरकार भी जातीय गणना नहीं करा रही है। जिस दिन देश में जातीय गणना हो जाएगी उस दिन सबको पता चल जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, उनको उसी हिसाब से उनके हक मिल सकेंगे। उसी दिन देश में हिन्दू-मुस्लिम का विवाद खड़ा करनेवाली राजनीति खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है। हम संकल्प लेते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

समाजवादी पार्टी में अन्य दलों से कई प्रमुख नेता लगातार शामिल हो रहे हैं। आप, खुद भी लगातार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। जनता के मन में क्या चल रहा है? आपको क्या लगता है?

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अपना आधे से ज्यादा कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अब तो तकरीबन 500 दिन ही बचे हैं इस सरकार के। 3 साल में इस सरकार ने जनता को इतना त्रस्त कर दिया है कि जनता बदलाव के लिए बेताब है, और उसकी पसंद समाजवादी पार्टी है क्योंकि भविष्य मारा है। इसलिए न सिर्फ अन्य दलों के नेता हमसे जुड़ रहे हैं बल्कि जहां भी मैं जा रहा हूं वहां लोगों का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। हम लोगों के भरोसे पर खरा उतरने कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

क्या आपको लगता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अपनी ही सरकार से बेहद नाराज हैं और दोबारा मुखर होंगे? जैसा कि विधानसभा में हो चुका है?

देखिए, इस सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस सरकार से खुद उसके ही विधायक नाराज हों उस सरकार के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का क्या रुख होगा इसका आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। सिर्फ बड़ी-बड़ी बातों से सरकार नहीं चलती, प्रदेश चलाने का स्पष्ट एजेंडा होना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार और उसके बड़बोले मुखिया ने ऐसे हालात बना दिए कि उनके विधायक की उनके खिलाफ धरने पर बैठे हैं। जहां इतना गुस्सा हो तो वह दोबारा किसी भी समय फिर से मुखर हो सकता है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या।

विधानसभा के चुनाव जैसे-जैसे करीब आएंगे स्वाभाविक रूप से आपके दौरे भी बढ़ेंगे और समाजवादी पार्टी भी और सक्रिय होगी। जनता के बीच आपकी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा?

उत्तर प्रदेश को फिर से विकास के रास्ते पर वापस लाना ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और आगे भी होगा, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं वहां लोग यही शिकायत करते हैं कि वह बेहद परेशान हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश विकास की पटरी से उतर गया है। लिहाजा समाज का हर तबका परेशान है। जनता सरकार से काम चाहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड "काम बोलता है" का ही रहा है। आगे भी जनता के सामने हमारा मुद्दा काम ही रहेगा क्योंकि समाजवादी कभी किसी के साथ जाति-धर्म, गरीब-अमीर, ऊंच-नीच के नाम पर भेदभाव नहीं करते। जबकि भाजपा तो सिर्फ झूठे नारे देकर लोगों के बहकाने का कार्य करती है।

जिस दिन देश में जातीय गणना हो जाएगी उस दिन सबको पता चल जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, उनको उसी हिसाब से उनके हक मिल सकेंगे।

बदलाव की आहट

बुलेटिन ब्यूरो

लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भीड़ हिलोरें ले रही है। कार्यालय प्रांगण का कोई हिस्सा खाली नहीं। हर कोना ठसाठस भरा। मकर संक्रांति के बाद की तेजी पकड़ती धूप और विदा लेते ठंड के मौसम के हवाले से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, "मौसम बदल रहा है...माहौल में गर्मी आ रही है... जैसे-जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव और करीब आता जाएगा, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में माहौल की गर्माहट और बढ़ती जाएगी।" राष्ट्रीय अध्यक्ष के इन शब्दों पर पूरा कार्यालय प्रांगण भीड़ की तालियों और नारों से देर तक गूंजता रहा।

जनवरी की जिस दोपहर, अखिलेश जी ने यह कहा, वह मौका बीते कुछ महीनों के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश की आम जनता और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बढ़ते भरोसे को स्पष्ट करने वाला एक और आयोजन था। जिस तरह अलग-अलग पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी को बदलाव का वाहक मानते हुए पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वह साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव की आहट तेज हो ही है और विकल्प समाजवादी पार्टी ही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से त्रस्त जनता बदलाव की बाट जोह रही है। जनता को अब यह बखूबी समझ में आने लगा है कि 3 साल की योगी सरकार में न तो धेले भर का विकास कार्य किया गया और न समाज में समरसता का भाव कायम किया गया।

बदलाव का यह माहौल सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में ही नहीं दिख रहा बल्कि उत्तर प्रदेश के जिस हिस्से में भी अखिलेश जी का दौरा हो रहा है वहां भारी भीड़ उन्हें देखने, उन्हें सुनने और उनसे हाथ मिलाने के लिए जुट रही

है। चाहे वह मौका सीएए और एनआरसी के खिलाफ जनता के विरोध प्रदर्शन में पुलिस ज्यादती के दौरान मारे गए नौजवानों के परिजनों से मिलने का अवसर हो या जनसंपर्क से जुड़ा हुआ दौरा। अखिलेश जी जहां भी पहुंच रहे हैं वहां जुट रही भीड़, जिसमें हर तबके, हर उम्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, यह संकेत देने के लिए पर्याप्त है कि जनता को अखिलेश जी की सरकार के दौरान किए गए विकास कार्यों और उनकी शासन चलाने कुशल क्षमता की कमी योगी सरकार में बुरी तरह खल रही है।

अभी हाल में अखिलेश जी एक कार्यक्रम के सिलसिले में सीतापुर जनपद पहुंचे तो कड़कड़ाती ठंड में भी देर रात तक लोग सड़क पर उनका स्वागत करने के लिए और उनकी बात सुनने के लिए इंतजार करते रहे। उनकी कार के पीछे भी लोग भाग रहे थे। रास्ते में स्वागत और लहरपुर की सभा की संख्या मिलाकर करीब एक लाख से ज्यादा लोग थे। लहरपुर के सबसे बड़े मैदान में हुई सभा में तिल रखने को जगह नहीं बची थी। लोगों का कहना था कि अखिलेश जी जम्हूरियत के तर्जुमान हैं। ऐसे दृश्य प्रदेश के कई और हिस्सों में भी देखने को मिल रहे हैं। झांसी हो, सुल्तानपुर हो, या फिर आजमगढ़ हर जगह ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं।

साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव की आहट तेज हो रही है और विकल्प समाजवादी पार्टी ही

योजनाओं का न सिर्फ उन्होंने खाका बनाया बल्कि हकीकत में जमीन पर भी उतारा। ठीक उसके उलट, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार विकास के नाम पर सिर्फ गाल बजा रही है। 3 साल हो गए मगर सड़कें ही अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अधर में लटका है स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति खराब है, स्कूलों में पढ़ने-पढ़ाने का कोई माहौल ही नहीं है।

करीब 3 साल पहले बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने घोषणापत्र को खुद ही भूल चुकी है। सरकार और उसके मुखिया का पूरा समय समाज में वैमनस्य पैदा करने और भेदभाव की राजनीति को बढ़ावा देने में निकल रहा है। कानून व्यवस्था सुधारने के सारे दावे चारों खाने चित है। महिलाओं के प्रति अपराध और साइबर क्राइम के मामले में यूपी सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन इससे बेखबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी ऐसे मुद्दों को एजेंडा बनाने में लगी हैं जिनसे जनता के विकास और उनके जीवन में खुशहाली आने का कोई संबंध नहीं है। शहरों के बाद भाजपा अब नदियों के नाम बदलने का खेल, खेल रही है। इस सच्चाई से बेखबर कि इससे नौजवानों को क्या हासिल होगा? इससे न रोजगार मिलेगा और नहीं भविष्य संवरेगा। लखनऊ में निवेश सम्मेलनों के बावजूद बाहर से निवेश नहीं आया है। उद्योग धंधे बंद हैं।

उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के उप चुनावों के नतीजों से भी साफ है जनता ने विपक्षी पार्टियों में समाजवादी पार्टी को ही अपना प्रतिनिधि माना और उसे कामयाबी दिलाई।

भाजपा सरकार के काले कारनामों, कुशासन और अराजकता से त्रस्त जनता मन बना चुकी है कि उसे श्री अखिलेश यादव को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को सत्ता दिलानी है। जनता के इसी मिजाज को भांपते हुए विभिन्न दलों के राजनेता समाजवादी पार्टी का तेजी से दामन थाम रहे हैं। वही योगी सरकार के कुशासन से प्रभावित हर तबका राहत के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर आकर अखिलेश जी से मिल रहा है। चाहे वह शिक्षक हों, युवा हों, वकील हों या फिर किसानों के प्रतिनिधि।

प्रदेश के अपने दौरे में अखिलेश जी भी जनता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमले बोल रहे हैं। वे बता रहे हैं कि कैसे गांधीजी की इस वर्ष 150वीं जयंती मनाई गई है, जिनका उनका सत्य-अहिंसा का रास्ता था और जो त्याग के हामी थे लेकिन भाजपा सत्य-अहिंसा के रास्ते से भटक कर भोगवादी बन गई है। भाजपा के राज में भारत की गरिमा गिर रही है। उसके राज्य में न्याय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है। भाजपा ने नोटबंदी, जीएसटी, एनपीआर में देश को उलझा कर रख दिया है। वे अपने भाषणों में राजनीति में मूल्यों की गिरावट पर लगातार गंभीर चिंता जता रहे हैं।

वह कह रहे हैं कि राजनीति में जैसी भाषा भाजपा नेता बोल रहे हैं उससे लोगों में भय व्याप्त हो रहा है। सीएए, एनआरसी और एनपीआर ने देश में बड़ी संख्या में लोगों के मन में तमाम आशंकाएं पैदा कर दी है क्योंकि यह गरीबों के

खिलाफ है, जगह जगह पर महिला आंदोलित हैं, विश्वविघालय में छात्रों में असंतोष है लेकिन इस इस सबसे सरकार बेखबर है। उसका व्यवहार अब मानवीय नहीं रह गया है। इन हालातों से ही जनता बदलाव चाहती है।

भाजपा का राज यानी..

- सीएए-एनपीआर लाकर ध्यान भटकाने की राजनीति
- समाज में अमनचैन नहीं
- हिंसा का रास्ता
- सामाजिक सद्भाव पर हमला
- सत्य से नफरत
- संविधान से खिलवाड़
- भाईचारा खत्म करने की साजिश
- किसान बदहाल
- भारी महंगाई
- चौपट कानून-व्यवस्था
- असुरक्षित बच्चियां व महिलाएं

युवा जोश

समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर इन दिनों बड़ी भीड़ जुट रही है। यह आम कार्यकर्ताओं की भीड़ है, आम लोगों की भीड़ है और यह भीड़ दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे नेताओं के समर्थकों की भी है। सबसे खास बात यह है कि यह भीड़ बेहद अनुशासित है। हाल के दिनों में जितने भी बड़े कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हुए उनमें कार्यकर्ताओं का अनुशासन बेहद उत्साहित करने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सपा प्रमुख द्वारा 18 वर्ष की आयु के नौजवानों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के कार्यक्रमों में भी ऐसा ही अनुशासन दिख रहा है।

अभी हाल में बस्ती के कद्दावर नेता राम प्रसाद चौधरी जब समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचे तो पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन लगी थी। जिसमें सपा के कार्यकर्ता तो थे ही, वही श्री चौधरी के समर्थक भी थे और सब कतारबद्ध होकर तब तो कर पार्टी कार्यालय में प्रवेश करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनुशासित कार्यकर्ता संयमित होने का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। जो कार्यकर्ता अन्य दलों से आए थे उनके लिए जगह बनाने व उन्हें पहले प्रवेश दिलाने में सपा की युवा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। न किसी की किसी से आगे निकल जाने की होड़ न धक्का-मुक्की।

इतना ही नहीं कार्यालय प्रांगण के मैदान में मंच संचालन और मंच पर नेताओं के प्रवेश को भी बेहद सुव्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। जो जो नेता मंच पर होंगे उनका नाम पहले सुरक्षाकर्मियों को दे दिया जा रहा है और सुरक्षाकर्मी पार्टी के वरिष्ठ व्यवस्थापक के साथ मिलकर मंच पर उन्हीं नेताओं का प्रवेश सुनिश्चित कर रहे हैं जिनके लिए पहले से निर्देश मिले हुए हैं। ऐसे में पूरा कार्यक्रम बेहद सुव्यवस्थित और अनुशासित तरीके से हो रहा है।

दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में अनुशासन को महत्व देने का निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की तरफ से दिए जाने का यह नतीजा है। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हाल के दिनों में जो जूही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं या

कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, वहां पर पहले की तरह अनावश्यक नारेबाजी करने या अखिलेश जी को अपना चेहरा दिखाने की होड़ पर खुद अखिलेश जी ने रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अखिलेश जी ने इस मामले में स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं जब भी कोई कार्यक्रम होगा अनावश्यक नारेबाजी नहीं होगी। खासतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो कतई नहीं। यह बहुत सुखद बात है कार्यकर्ता अपने नेता के इस निर्देश को अक्षरश: से पालन करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, खासतौर पर युवा कार्यकर्ताओं के बीच यह संदेश अब धीरे-धीरे नीचे की तरफ जा रहा है कि पार्टी में उनका अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। अभी हाल में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव ने इस बात पर खुशी जताई कि बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में जुटे हैं। पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में युवा हैं और युवाओं के हाथों में सपा का भविष्य सुरक्षित है। युवा कार्यकर्ताओं का यह अनुशासित व्यवहार इसकी तस्दीक करता है कि सपा के युवा कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे अनुशासित सिपाही की तरह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कंधे से कंधा मिलाकर 2022 में अपने नेता को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं।

#काम बोलता है

समाजवादी पार्टी

अखिलेश के जनसंपर्क दौरों से जनता में उल्लास, उमड़ रही भीड़

राजेन्द्र चौधरी
राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी

नव वर्ष सन् 2020 की शुरुआत के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 2022 में होने वाले चुनावों को दृष्टि में रखते हुए अपनी सघन तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्री यादव ने नए साल के शुरुआत महीनों में ही करीब दो दर्जन जनपदों में लाखों लोगों से सम्पर्क किया है।

उनकी सड़क मार्ग से हुई इन सामाजिक-राजनीतिक यात्राओं में जगह-जगह जो भीड़ उमड़ी वह अप्रत्याशित और स्वतः स्फूर्त है। यह स्पष्ट संकेत है कि भाजपा के प्रति जनाक्रोश बढ़ा है। लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प में अखिलेश जी पर उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है।

श्री अखिलेश यादव जब भी कहीं चलते हैं, तत्काल सूचना पाकर भी बड़ी तादाद में लोग जुट जाते हैं। पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, जनता जनार्दन भी हजारों की तादाद में उनको देखने-सुनने के लिए एकत्र हो रही है। अखिलेश जी का स्वागत करने वाले भाजपा के प्रति अपने गुस्से का भी खुलकर इज़हार करते है। जगह-जगह नारे लगते हैं, 'तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का, राज बदल दो।'

बहराइच

9 फरवरी 2020 को श्री अखिलेश यादव जनपद बहराइच के भ्रमण पर रहे। तराई के इस क्षेत्र के दौरे में गांव-किसान की बदहाली और नौजवानों की बेरोजगारी पर उनकी लगातार निगाह रही। श्री अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा के रास्ते में खेतों में पीली सरसों की छटा देख कहा कि किसान इतनी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। भाजपा सरकार किसानों को ड्योढ़े दाम दिलाने, आमदनी दुगनी करने के झांसे दिलाती रही है। वहीं नोटबंदी और जीएसटी की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। मंहगाई की मार से आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार तीन साल हो गए अपनी एक भी जनहित की योजना लागू नहीं कर सकी।

लखनऊ से चलकर बाराबंकी पहुंचते ही जिलाध्यक्ष श्री अयाज अहमद स्थानीय लोगों व विधायकों के साथ स्वागत में खड़े मिले। जबकि रामनगर बाराबंकी में पार्टी कार्यालय पर पूर्व मंत्री श्री अरविन्द सिंह गोप ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ज़ोरदार स्वागत किया। यहां भी सैकड़ों लोगों ने अपने प्रिय नेता के जिंदाबाद के जोरदार

नारे लगाए। जरवल से गोण्डा फोरलेन रोड पर घाघरा नदी पुल पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एवं जनता मौजूद थी। यहां पूर्व मंत्री विनोद कुमार

सिंह उर्फ पंडित सिंह ने श्री अखिलेश यादव का स्वागत किया तो स्थानीय रेलवे स्टेशन पर अपने साथियों के साथ संजय विधार्थी सविता स्वागत में मौजूद थे।

कैसरगंज में पूर्व विधायक श्री रामतेज यादव स्वागत में खड़े मिले और वहां उनके साथ तमाम मौलाना अखिलेश जी को दुआएं दे रहे थे। धनराजपुर, जरवल कस्बा और नन्दोलिया में छात्रों ने स्वागत किया। पयागपुर में पुरनिया चौराहे पर पूर्व विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव, प्रमोद यादव आदि ने और हजूरपुर में गौड़िया निषाद मल्लाहों ने, जबकि बाजार में कुंवर जयंकर सिंह, आनंद शेखर सिंह और धर्मदेव प्रधान ने, लोधेकाही बाजार में श्री दिनेश प्रताप सिंह प्रधान ने स्वागत किया। पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव द्वारा आयोजित स्वागत सभा में हजारों की भीड़ थी, जिसे अखिलेश जी ने सम्बोधित भी किया।

पयागपुर में उपस्थित हजारो किसानों, नौजवानों ने एक स्वर में कहा कि सन् 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। यहां पूर्व मंत्री श्री याशर शाह भी थे। रास्ते में गरीब श्रमिक और महिलाएं गन्ने के खेत में बहुत ही न्यूनतम मजदूरी पर काम करते हुए मिलीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाड़ी से उतर कर उनके पास गए और वार्ता के क्रम में उन्होंने कहा कि इस बार समाजवादी सरकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके पूर्व पयागपुर के राज महल में राजमाता की उपस्थिति में नवविवाहित दम्पति राजा सर्वेन्द्र विक्रम सिंह एवं उनकी सहधर्मिणी को सफल दाम्पत्य जीवन की अखिलेश जी ने शुभकामनाएं दी।

पयागपुर से लखनऊ लौटते समय सिम्भवली शूगर मिल के पास केहौली गांव में विजय साह

चिलवरिया, बहराइच में महसी के पूर्व विधायक श्री केके ओझा के आवास पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का स्वागत किया गया। बहराइच के टिकोरा मोड़ पर चिरारीघाट में श्री राजेश तिवारी एडवोकेट ने स्वागत किया। फखरपुर में वरिष्ठ नेता श्री शब्बीर बाल्मीकि तथा श्रीमती निशा शर्मा ने स्वागत किया।

झांसी-आजमगढ़-सुल्तानपुर

श्री अखिलेश यादव ने विगत 28 जनवरी 2020 को झांसी की मोठ तहसील की यात्रा की और 29 जनवरी 2020 को आजमगढ़ के कार्यक्रमों में शिरकत की। झांसी की मोठ तहसील की यात्रा का कुछ अलग ही महत्व था। यहां श्री अखिलेश यादव दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविधालय (जेएनयू) के एक नव दम्पत्ति डा० दिलीप यादव एवं इंजीनियर पल्लवी नन्देश्वर के अंतर्जातीय विवाह समारोह में आशीर्वाद देने पहुंचे थे। इस मौके पर पृष्ठभूमि में डा० अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, डा० राममनोहर लोहिया जहां आशीर्वाद की मुद्रा में थे वहीं सांसद डा० चन्द्रपाल यादव, दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव, उदयवीर सिंह एमएलसी सहित छात्र जेएनयू में अध्ययनरत साथियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। दिलीप-पल्लवी के विवाह समारोह में गरीब किसान, समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता भी शामिल हुए।

डा०. लोहिया का तो यही कहना था कि जाति

प्रथा के विरोध से ही देश में एक नई सोच आएगी। डा० लोहिया ने अपनी 'सप्तक्रांति' की अवधारणा में नर-नारी समानता को प्रथम स्थान दिया था। वे कहते थे स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देकर ही एक स्वस्थ और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण किया जा सकता है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि जिस भेदभाव की वजह से सामाजिक जीवन में अलग-अलग गुट हैं और जाति-जाति में वि द्वेष और दुश्मनी पैदा हुई है उस जातीयता का त्याग होना ही चाहिए। डा॰. अम्बेडकर का स्पष्ट मत था कि जाति व्यवस्था तोड़ने का एक मात्र उपाय है अंतर्जातीय विवाह। पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह भी जातिप्रथा के विरुद्ध थे और वे इसके उन्मूलन के लिए अंतर्जातीय विवाहों पर विशेष बल देते थे।

झांसी यात्रा के दौरान कालपी जाते हुए ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर में कूड़े के ढेर पर गायों के झुण्ड द्वारा प्लास्टिक खाते देखकर श्री अखिलेश यादव का मन खिन्न हो उठा। उन्होंने कहा क्या यही स्वच्छ भारत है? क्या यही गोसेवा की भावना है? बाते राज्य सरकार बड़ी-बड़ी करती है लेकिन गाएं गोशालाओं में मर रही है। सड़कों पर घूमती गायों की देखभाल नहीं होती है। कूड़े की प्लास्टिक खाकर गौमाता अपनी जान गंवा रही है। आजमगढ़ में उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में हिन्दू-मुस्लिम ने बराबरी से कुर्बानी दी थी। आज उनके बीच वैमनस्य के बीज बोए जा रहे है। कर्ज से परेशान किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। उनको फसल का न तो लागत मूल्य मिल रहा है और नहीं उसकी आय दुगनी हो रही है। नदियों की सफाई की भाजपा ने मजाक बना दिया है। जब तक काली, हिंडन, वरूणा नदियां साफ नहीं होती गंगा-यमुना की निर्मलता की उम्मीद नहीं हो सकती है। यह खतरनाक स्थिति है।

जनपद आजमगढ़ में श्री अखिलेश यादव अम्बारी गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय रामकृष्ण यादव के आवास व उनके पट्टीदार तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री रामनरेश यादव के आवास पर भी गए। बुजुर्ग रामफर ने श्री अखिलेश यादव से कहा कि उनके पास तो कागज नहीं है फिर सीएए, एनपीआर, एनआरसी में क्या दिखा सकेंगे। प्रधान जमील अहमद भी यही कह रहे थे। यहां अखिलेश जी ने चौधरी चरण सिंह के पुराने साथी रहे श्री राम बचन यादव को भी याद किया। अखिलेश जी ने अम्बारी में बांके यादव की चाय की दुकान पर चाय पी। श्री अखिलेश यादव का लखनऊ से आजमगढ़ और आजमगढ़ से लखनऊ की यात्रा के दौरान जगह-जगह भव्य स्वागत हुआ।

पूर्व सांसद सर्वश्री दारोगा सरोज, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सुभाष राय, आशुतोष उपाध्याय, राकेश यादव एमएलसी, विधायक संग्राम सिंह यादव, पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, पूर्व विधायक बेचईराम, कमला प्रसाद यादव, श्याम बहादुर यादव, अखण्ड प्रताप यादव जिलाध्यक्ष, श्री प्रेम प्रकाश जायसवाल उपाध्यक्ष, जितेन्द्र वर्मा, मिथलेश यादव पूर्व प्रमुख, श्री विक्रम बिन्द के नेतृत्व में स्वागत किया गया। श्री अखिलेश यादव शाहगंज, जौनपुर में श्री शैलेन्द्र यादव ललई के आवास पर भी गए। सुल्तानपुर में जवान, महिलाएं तथा बुजुर्ग हजारों की संख्या में अखिलेश जी से मिलने और उनको देखने-सुनने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े हुए नारा लगा रहे थे कि हम आपके साथ हैं। कुछ बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा कि संकट से उबारिए, आप फिर सरकार में आइए। यहां दियरा चैराहे पर श्री अरूण वर्मा पूर्व विधायक उनका स्वागत किया।

सीतापुर

इससे पहले श्री अखिलेश यादव ने 15 जनवरी 2020 को सीतापुर में कई कार्यक्रमों में भाग लिया। लहरपुर में उनकी ऐतिहासिक सभा हुई जिसमें कल्पनातीत भीड़ उमड़ी। नौजवान, किसान, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं दूर-दूर से पार्टी के झण्डे लिए अखिलेश यादव जिन्दाबाद के नारे लगाते सभास्थल पर आते रहे। उनकी कार के पीछे भी लोग भाग रहे थे। रास्ते में स्वागत और सभा की संख्या जोड़ ले तो करीब एक लाख से ज्यादा लोग थे। लोगों का कहना था कि श्री यादव जम्हूरियत के तर्जुमान है। कल लहरपुर के सबसे बड़े मैदान में तिल रखने को जगह नहीं बची थी।

श्री अखिलेश यादव लहरपुर पूर्व सांसद, श्री हरगोविन्द वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इस मौके पर स्वर्गीय हरगोविन्द वर्मा के पुत्र पूर्व विधायक श्री अनिल वर्मा, जिलाध्यक्ष श्री छत्रपाल सिंह यादव, विधायक श्री नरेन्द्र वर्मा, पूर्व विधायकगण निर्मल वर्मा, रामपाल राजवंशी, अनूप गुप्ता, झीनबाबू के अतिरिक्त श्रीमती गीता सिंह, शमीम कौसर सिद्दीकी, विकास यादव, दिग्विजय सिंह देव, फिदाहुसैन अंसारी भी उपस्थित थे।

सैफई में लहराया 155 फीट ऊंचा तिरंगा

सैफई में 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने हजारों कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों के बीच ध्वजारोहण किया। सैफई में बड़े आकार का राष्ट्रध्वज 155 फीट ऊंचाई के पोल पर लहराया गया। इससे पूर्व सैफई पहुंचने पर श्री अखिलेश यादव तथा राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं सांसद प्रो. रामगोपाल यादव के द्वारा पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं गांधी शान्ती मार्च के नेता श्री यशवंत सिन्हा का शाल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सैफई के गणतंत्र दिवस समारोह में श्री अखिलेश यादव के साथ प्रो. रामगोपाल यादव, यशवंत सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव राजेन्द्र चौधरी, पूर्व सांसद धर्मेन्द्र यादव एवं तेज प्रताप यादव तथा विधायक डा॰ दिलीप यादव, राज कुमार राजू, सहित अनुराग यादव, अंशुल यादव तथा हजारों लोग मौजूद थे।

श्री अखिलेश यादव ने 50 हजार से अधिक की विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि गांधीजी की इस वर्ष 150वीं जयंती मनाई गई है। उनका सत्य-अहिंसा का रास्ता था। वह त्याग के हामी थे। भाजपा सत्य-अहिंसा के रास्ते से भटक गई है। भाजपा इसकी व्यवस्था करती है कि समाज में अमनचैन न रहे। उसका रास्ता हिंसा का है। सत्य से उसे नफरत है। संविधान से खिलवाड़ करना उनका तरीका है। भाजपा भाईचारा खत्म कर रही है। शहरों के बाद अब नदियों के नाम बदलने का खेल, खेल रहे हैं। इससे नौजवानों को क्या हासिल होगा? इससे न रोजगार मिलेगा और नहीं भविष्य संवरेगा। बाहर से निवेश नहीं आया है। उद्योग धंधे बंद है।

उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं बची है। प्रशासन पंगु है। मंत्रियों में तालमेल नही है। जनता के काम नहीं हो रहे है। भाजपा विधायक भी असंतुष्ट है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दो ट्रक सुरक्षाकर्मियों के साये में चलता है। जनता की सुरक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में कानून- व्यवस्था चौपट है। घूसखोरी और रिश्वतखोरी छुपाने के इरादे से ही भाजपा सरकार ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है।

श्री यादव ने बिसवां में हजरत गुलजार शाह रहमतुल्ला अलैह की मजार पर चादर चढ़ाई। अखिलेश जी ने शंकर जी के शिवाला मंदिर पर पूजा अर्चना की। महमूदाबाद में अखिलेश जी ने उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

श्री अखिलेश यादव का लखनऊ से सीतापुर जाते हुए इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ पर

सर्वश्री विजय यादव, गोमती यादव, पूर्व विधायक ने और कमला यादव एवं राम सिंह राणा ने अपने तमाम साथियों के साथ स्वागत किया।

बख्शी का तालब में सर्वश्री विदेश यादव, सुभाष यादव, दिनेश कुमार सिंह, सागर यादव ने, अटरिया में श्री नरेन्द्र वर्मा और श्री विशाल वर्मा, सिधौली सीमा पर प्रधान अंशू शर्मा, सिधोली में पूर्व विधायक श्री मनीष रावत और अमर सिंह बबलू ने भी स्वागत किया। रास्ते में पूर्व सांसद श्रीमती सुशीला सरोज और अध्यक्ष जिला पंचायत सीतापुर श्री जितेन्द्र यादव ने स्वागत किया। सीतापुर से पहले टोलप्लाजा पर श्री आनन्द भदौरिया और श्री राधेश्याम जायसवाल ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ स्वागत किया। सैरियां पर श्री दिग्विजय सिंह देव तथा विनय यादव ने अपने नेता का स्वागत किया।

खैराबाद में श्री सचिन जायसवाल, हाजी जलीस अहमद अंसारी ने स्वागत किया। आफाक दरी की फैक्ट्री में, कसैरैला रेलवे क्रासिंग में तथा मेंहदीपुरवा में पूर्व सांसद श्री मुख्तार अनीस, जहीर अब्बास, ने श्री अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। हाजी जावेद के भट्टा पर भी स्वागत हुआ।

श्री अखिलेश यादव की सीतापुर से लखनऊ वापसी में हरदोई चुंगी सीतापुर में श्री आनन्द भदौरिया, श्री विवेक वर्मा एवं श्री चंद्र प्रकाश शर्मा ने कुर्सी में श्री फरीद महफूज किदवई पूर्व मंत्री तथा एमएलसी श्री राजेश यादव राजू ने और रीवां शीवां चैकी, बाराबंकी में पूर्व मंत्री श्री अरविन्द सिंह गोप तथा सुरेश यादव एमएलए ने स्वागत किया। यद्यपि खराब मौसम और बारिश के कारण अखिलेश जी चार घंटे देरी से पहुंचे लेकिन इसके बावजूद भारी भीड़ उनका इंतजार करती रही। अनवारी गांव में प्रधान बद्दूपुर हाफिज अंसार तथा चौधरी अदनान ने, बेहटा बाजार में श्री सुभाष यादव ने गुडम्बा में श्रीमती प्रेमलता यादव के अलावा टेढ़ी पुलिया लखनऊ में श्री सिमरन खां और श्रीमती विभा शुक्ला ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया।

कानपुर/कन्नौज

9 जनवरी 2020 को अखिलेश जी ने कानपुर पहुंचकर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए मुंशीपुरवा के मोहम्मद सैफ, मोहम्मद आफताब और मोहम्मद रईस के परिजनों से भेंट की। ये बेहद गरीब परिवार के हैं। श्री यादव ने मृतक आश्रितों को सांत्वना दी और सैफ के पिता मोहम्मद तकी, आफताब की माता श्रीमती नजमा बानो तथा रईस के पिता श्री शरीफ को 5-5 लाख रुपए के चेक देकर आर्थिक सहायता दी। श्री अखिलेश यादव ने इसके पूर्व लखनऊ में मृतक वकील अहमद के परिजनों से भेंट कर उन्हें 5 लाख रुपए का चेक दिया था। अखिलेश जी की कानपुर यात्रा में पच्चीस हजार से ज्यादा नौजवानों की भीड़ उमड़ी। इनमें बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं तथा युवा शामिल थे। कानपुर में भीड़ का आलम यह था कि भारी पुलिस बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) भी व्यवस्था बनाए रखने में सफल नहीं हो

सकी। नौजवानों में भाजपा सरकार और प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश । तब स्वयं अखिलेश जी ने किसी तरह स्थिति को संभाला।

14 जनवरी 2020 को श्री अखिलेश यादव ने कन्नौज के छिबरामऊ के निकट बस-ट्रक भिड़ंत में, जिस स्थल पर बस में जलकर यात्रियों की मौत हुई थी, वहां दो मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारीजनों से संवेदना व्यक्त की। उन्होने तिर्वा मेडिकल कालेज में घायलों से भी भेंट की।

श्री यादव ने बस दुर्घटना के मृतक आश्रितों को भरोसा दिया कि समाजवादी सरकार बनने पर उन्हें 20-20 लाख रूपए की मुआवजा राशि देकर मदद की जाएगी। उन्होंने राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज में भर्ती मरीजों को देखने के बाद कहा कि भाजपा सरकार इलाज में भी भेदभाव कर रही है। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि मुस्लिमों के इलाज में कोताही बरती जा रही है। उन्होने छिबरामऊ में गैस सिलेण्डर के हादसे में मृतक आश्रितों से भी भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। लखनऊ से छिबरामऊ के रास्ते में सड़को पर जगह-जगह स्वतः स्फूर्त ढंग से नौजवान, महिलाएं, किसान एकत्र हो गए थे। उन्होने श्री अखिलेश यादव की 2022 में सरकार बनने की कामना की।

भाजपा राज में सेना को न पौष्टिक खाना न जूते

बुलेटिन ब्यूरो

भाषणों में सेना के शौर्य को चुनावी लाभ के लिए भुनाने की कोई कसर न छोड़ने वाली केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने दरअसल दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। सियाचिन, लद्दाख और डोकलाम में तैनात सैनिकों को पौष्टिक भोजन की कमी, बर्फ पर चमकती तेज धूप से बचने के लिए लगाए जाने वाले चश्मे और जूते तक नहीं मिल रहे। यह खुलासा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएजी) की जांच में हुआ है।

सियाचिन, लद्दाख, डोकलाम जैसे ऊंचे व बर्फीले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को उनके भोजन में जरूरत के मुताबिक कैलरी नहीं मिल पाई। वहां के मौसम से निपटने के लिए जिस तरह के विशेष कपड़ों की जरूरत होती है, उसकी खरीद में भी काफी देर हुई। पुराने पैमाने से ही बनने वाले कपड़े और उपकरण मिलने से इन क्षेत्रों में तैनात सैनिक बेहतर कपड़े और उपकरणों से वंचित रहे। संसद के वर्तमान सत्र में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट से इस गंभीर स्थिति व लापरवाही का खुलासा हुआ है। सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के दौरान की है।

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए आहार की व्यवस्था में उनकी रोजाना की ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन नियमों की अनदेखी से सैनिकों के लिए जरूरी कैलरी की मात्रा कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी कमांड में खुले टेंडर से ठेका दिया गया जबकि उत्तरी कमांड में सीमित टेंडरिंग से खरीद की गई। निष्पक्ष व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई ।

ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों को वहां की जरूरतों के हिसाब से कपड़े खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने साल 2007 में एक कमेटी बनाई थी ताकि खरीद में तेजी आ सके। इसके बावजूद इन दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कपड़ों की आपूर्ति में काफी देरी हुई। इसमें कहा गया है कि खरीद प्रक्रिया में विलंब के कारण सैनिकों का स्वास्थ्य और साफ-सफाई भी प्रभावित हुआ। चेहरे की मास्क, जैकेट, स्लीपिंग बैग भी पुराने पैमानों को आधार बनाकर खरीद लिए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रक्षा मामलों की प्रयोगशाला में शोध कार्यों की कमी और स्वदेशीकरण में नाकामी के कारण आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता रही।

उल्लेखनीय है कि साल 2017 में सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव ने जम्मू में सीमा रेखा पर तैनाती के दौरान खराब खाना मिलने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उस पर जरूरी कार्रवाई करने की बजाय तेज बहादुर पर ही कार्रवाई कर दी गई थी। इससे पहले भी संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में भारतीय सेना और सुरक्षा तैयारियों पर चिंता जताई जा चुकी है। यानी जमीन पर स्थिति को ठीक करने की बजाय मोदी सरकार चुनावी भाषणों में सेना का इस्तेमाल कर चुनावी लाभ लेने पर ही ज्यादा जोर देती है।

चुनाव निपटते ही किसान योजना का बस्ता गोल!

बुलेटिन ब्यूरो

देश के पांच करोड़ से अधिक किसानों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना की तीसरी किस्त के पैसे मिलने का इंतजार है। केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों में यह बात सामने आई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने खूब तामझाम से यह योजना शुरू की थी। चुनाव में निपटते ही इसका अब बस्ता गोल है।

छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देने के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत सरकार ने उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक की आर्थिक मदद देने की बात कही थी। दिसंबर 2018 से शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों को हर चार माह में 2,000-2,000 रुपये की किस्त दी जानी है। समाचार एजेंसियों की खबरों के मुताबिक सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार करीब 2.51 करोड़ किसानों को योजना की दूसरी किस्त भी नहीं मिली है। वहीं 5.16 करोड़ किसानों को अभी तीसरी किस्त मिलने का इंतजार है।

दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 के बीच योजना के तहत नौ करोड़ से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया। इसमें से तीसरी किस्त का लाभ मात्र 3.85 करोड़ किसानों को ही मिला है। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के बीच योजना के तहत कुल 4.74 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 4.02 करोड़ किसानों को पहली किस्त, 4.02 करोड़ को दूसरी किस्त और 3.85 करोड़ किसानों को तीसरी किस्त का लाभ मिला है।

हालांकि आरटीआई के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि शुरुआत में पंजीकृत करीब 50 लाख किसानों को पहली किस्त का, 70 लाख किसानों को दूसरी किस्त का और 90 लाख किसानों को तीसरी किस्त का लाभ क्यों नहीं मिला है। अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 के बीच इस योजना के तहत 3.08 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। आरटीआई के जवाब में यह नहीं बताया गया है कि इस अवधि में पंजीकृत करीब 40 लाख किसानों को पहली और 61 लाख किसानों को दूसरी किस्त का लाभ क्यों नहीं मिला।

मंत्रालय ने बताया है कि अगस्त 2019 से नवंबर 2019 के बीच करीब 1.19 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया। हालांकि इस अवधि के लिए मान्य पहली किस्त का लाभ 45 लाख किसानों को नहीं मिलने की कोई जानकारी मंत्रालय ने नहीं दी है। आरटीआई में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कुल किसानों की राज्यवार जानकारी मांगी गयी थी।

नाकारा सरकार, ध्वस्त कानून-व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में भाजपा के राज में कानून-व्यवस्था बुरी तरह ध्वस्त है। नाकारा सरकार में किसी की सुनवाई नहीं। नए साल के शुरूआती माह जनवरी 2020 में ही हत्या और बलात्कार की करीब एक-एक दजर्न घटनाओं को बेखौफ अपराधियों ने अंजाम दिया। ये वह वाकए हैं जिनकी जानकारी सामने आई वरना यह आंकड़े कहीं ज्यादा हैं।

अनुभवहीन मुखिया वाली इस सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है। हालत यह है कि सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ही अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठते हैं वहीं नौकरशाही तदर्थवाद और अस्थाई व्यवस्था के भरोसे चलाई जा रही है। अलबत्ता मुख्यमंत्री स्थिति पर उनका नियंत्रण होने का मुगालता पाले बैठे हैं। जबकि हकीकत यह है की ढाई मुख्यमंत्रियों वाली यह सरकार जनता की नजरों में बुरी तरह फेल साबित हो चुकी है।

सत्ता के गलियारों में योगी की बेबसी की चर्चा है। प्रदेश में शासन के दो अहम पदों मुख्य सचिव व डीजीपी पद पर लंबे समय तक स्थाई तैनाती ही नहीं हो पाने का हवाला दिया जा रहा है। कई महीनों तक कार्यवाहक मुख्य सचिव की व्यवस्था चलाने के बाद उसी अफसर की नियमित तैनाती हुई। इतने महीनों तक शासन के शीर्ष पद पर कार्यवाहक व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कभी नहीं रही। डीजीपी के पद पर अभी भी कार्यवाहक वाली व्यवस्था ही चल रही है और यह रिपोर्ट लिखे जाने तक किसी की नियमित तैनाती नहीं हुई है। इन दोनों अहम पदों पर तैनाती को लेकर इस तरह के असमंजस से स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है? सरकार चलाने का यह बेढब तरीका तब है जबकि भाजपा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में भारी जनादेश के दावे करते थकता नहीं है। यह चर्चा जोरों पर है कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के कारण राजकाज ठप हो गया है।

राजधानी लखनऊ में भी लगातार हत्याएं हो रही हैं। अपराधों से इतर नज़र डालें तो ऊर्जा निगम का पीएफ घोटाला, होमगार्ड ड्यूटी घोटाला और ताज़ा-ताजा पंचायतीराज में हुआ घोटाला भी इसी यूपी में हुआ है।

जिस सूबे में दहलाने वाले अपराधों की यह तस्वीर हो, विभागों में घोटाले सरकार रहते हुए उजागर हो रहे हों, वहां विभागों के मुखिया की कुर्सी ही तीन पायों की हो तो आप क्या कहेंगे? कार्यपालिका लड़खड़ाती दिख रही है। सितम्बर 2019 से मुख्य सचिव के पद पर कार्यवाहक बंदोबस्त के बाद अब जाकर फरवरी में नियमित तैनाती हुई।

जंगल राज

हत्या

चित्रकूट – बालाजी मंदिर के महंत की गोली मारकर हत्या

चित्रकूट – बरगढ़ थाना क्षेत्र में किसान की हत्या

चित्रकूट – राजपुर थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ी से काटकर कृषक की हत्या

मथुरा – बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की गोली मारकर हत्या

सुल्तानपुर -गोली मारकर दुकानदार की हत्या

बिजनौर – 2 सगे भाइयों की निर्मम हत्या

रायबरेली – अपहरण के बाद किराना व्यवसाई की हत्या

प्रयागराज – हाईकोर्ट के वकील की घर में हत्या

बलरामपुर –सोनौगढ़ी में किशोर को ज़िंदा जलाया

नोएडा – निजी कंपनी के रीजनल मैनेजर की हत्या

बलात्कार

नोएडा – 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म

बस्ती – 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म

प्रतापगढ़ – युवती से सामूहिक दुष्कर्म

रामपुर – किशोरी से तमंचे के बल पर दुष्कर्म

हाथरस – किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म

गोरखपुर – किशोरी से दुष्कर्म

कुशीनगर – 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म

इटावा – घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म

प्रयागराज – 6 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद दुपट्टे से गला घोंटा

कानपुर – भाजपा नेता की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म

बलिया - - किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म

(जनवरी 2020 तक के प्रमुख आंकड़े)

Akhilesh Yadav

@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Following

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Feb 14

भाजपाई कार्यकर्ताओं के गुंडाराज की एक और शर्मनाक घटना में कानपुर देहात के मांगटा गाँव में दलितों को जमकर पीटा गया जिसमें 23 दलित ज़ख़्मी हुए हैं. प्रदेश में पुलिस को अपनी रक्षात्मक भूमिका के विपरीत कार्य करने को बाध्य किया जा रहा है. हम इस लड़ाई में हर क़दम दलितों के साथ हैं.

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Feb 11

दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि अधिकांश भारतीय आज भी सामाजिक रूप से उदार व राजनीतिक रूप से समझदार हैं व धर्म जैसे व्यक्तिगत विषय को राजनीति के पंक में घसीटकर अपना सियासी फूल खिलानेवालों के ख़िलाफ़ हैं.

ये देश की शांति व विकास के लिए शुभ संकेत व स्वस्थ संदेश भी है.

#KaamBoltaHai

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Feb 16

देश की राजनीति व्यक्तिगत धमकियों से होती हुई सार्वजनिक मंचों पर षड्यंत्रकारियों तक को भेजकर राजनेताओं को बदनाम करने की साज़िश के निकृष्टतम दौर से गुजर रही है. लेकिन आज की समझदार जनता सब समझकर सत्ताधारियों के झाँसे में नहीं आनेवाली बल्कि सत्ता का विरोध करनेवालों के साथ खडी है.

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · 20h

'बदला-बाबा' अब क्या करेंगे? अब इस फैसले का बदला किससे लेंगे??

मुखिया हैं तो क़ायदे-क़ानून का इल्म भी होना चाहिए और इंसाफ़ की नियत और निगाह भी. ये पद ज़िम्मेदारी का है प्रतिशोध की ज़हरीली भाषा बोलने का नहीं.

> **CAA: लोगों से नहीं होगी हिंसा से नुकसान की भरपाई, HC ने लगाई योगी सरकार के फैसले पर रोक**
>
> याचिकाकर्ता का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इसके तहत लोक संपत्ति के नुकसान का आंकलन करने का अधिकार हाईकोर्ट के सीटिंग या सेवानिवृत्त जज अथवा जिला जज को है.

Akhilesh Yadav @yadavakhilesh · Feb 4

ये परदेस नहीं लखनऊ है!

ये है समाजवादी सरकार के समय बना 'गोमती रिवर फ्रंट'!

साफ़ और बेबाक

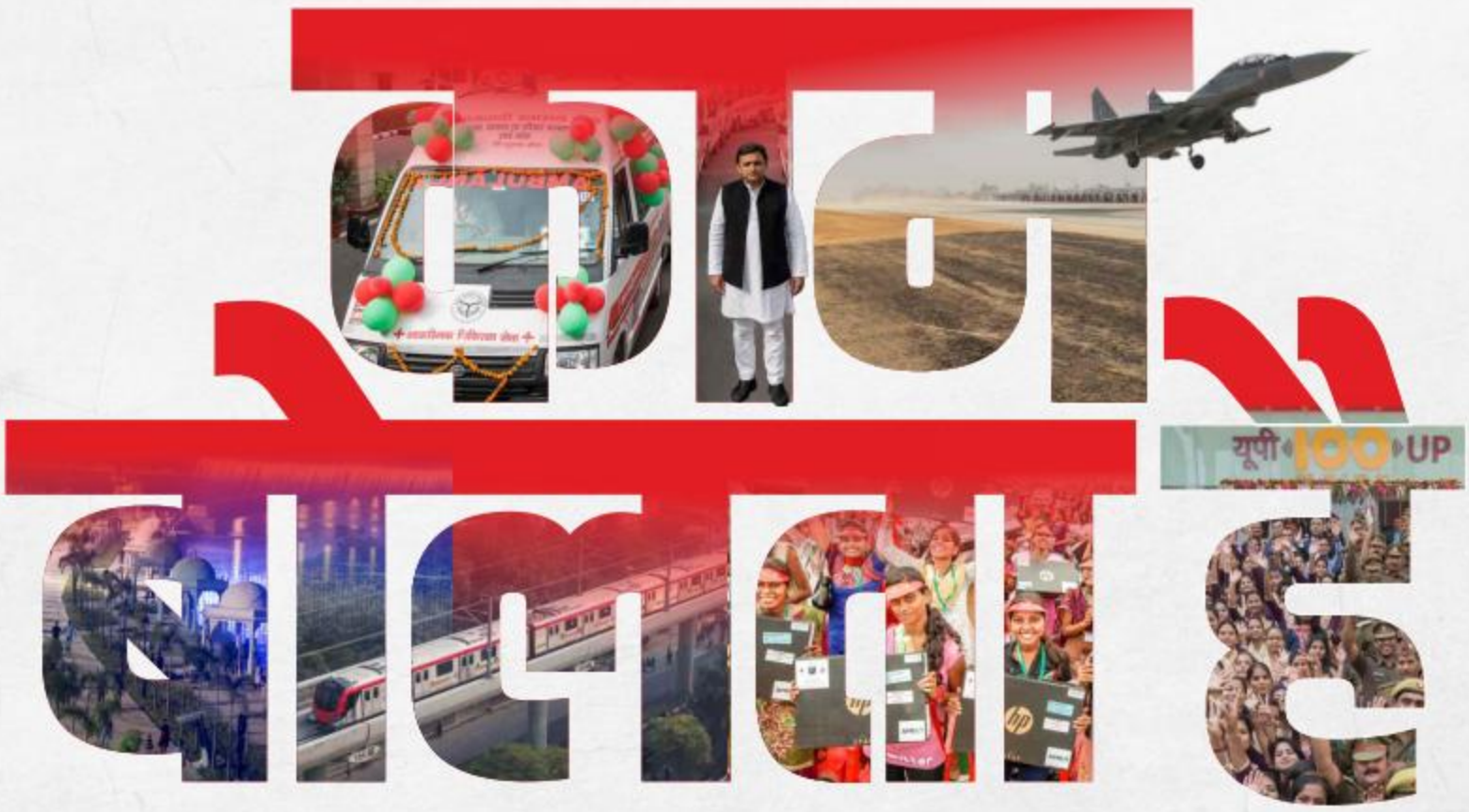

www.samajwadiparty.in